सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 154, नई दिल्ली । बुधवार, 14 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 महिला को दे सकती है बीजेपी अध्यक्ष की कमान?

06 आजादी के सही मायने की तलाश में

08 भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाल मनाया आजादी का जश्न...

क्या किसी स्वतंत्र निकाय/ निगम की संपत्ति पर दूसरा सरकारी विभाग या राज्य सरकार कब्जा कर सकते है एवं अन्य किसी को उपयोग के लिए दे सकते है, बड़ा सवाल?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम एक स्वतंत्र निकाय/ निगम है यह बात सर्वविदित है।

1. क्या नियम और कानून के अनुसार परिवहन निगम की संपत्ति पर परिवहन विभाग अपना वर्चस्व दिखा सकती है या उसकी संपत्ति को अपने कार्यों के लिए प्रयोग कर सकती है ?

2. क्या परिवहन विभाग/ दिल्ली सरकार परिवहन निगम की संपत्ति को अन्य कंपनियों को प्रयोग के लिए प्रदान कर सकते है?

3. क्या क्लस्टर कंपनियों की बसों एवम् अन्य कंपनियों के नाम पंजीकृत बसों को परिवहन निगम के डिपो/ संपत्ति कानून/ नियम में दिए जा सकते है?

4. क्या परिवहन निगम की संपत्ति दिल्ली परिवहन विभाग/ दिल्ली सरकार अन्य किसी के द्वारा प्रयोग करने के लिए निर्माण करवा सकते हैं ?

दिल्ली सरकार/ परिवहन विभाग के द्वारा लगातार परिवहन निगम की संपत्ति पर कब्जा और साथ ही निगम की संपत्ति को अन्य कंपनियों को सुपुर्द करने के विज्ञापन आने के बाद भी दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल द्वारा सवाल पूछने की जगह स्वयं उनके साथ खड़े होकर हरी झंडी दिखाना, क्या दर्शाता है

क्या है अंदर का सच जो जनता से अभी तक छुपाया हुआ है कृप्या उसे उजागर करे दिल्ली परिवहन निगम के नाम 11 साल में एक भी बस ना खरीदना,

दिल्ली परिवहन निगम में एक भी पद पर भर्ती नहीं करना,

दिल्ली परिवहन निगम के कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों/ अधिकारियों को पक्का नहीं करना और

दिल्ली परिवहन निगम की संपत्ति को अन्य कंपनियों को प्रयोग करने के लिए सुपुर्द करने के अलावा

दिल्ली परिवहन विभाग के मुख्यालय के लिए निगम के मुख्यालय का प्रयोग करना।

आख़िर इस सबके पीछे का सच क्या है और क्यों दिल्ली के उपराज्यपाल इस कार्य में दिल्ली परिवहन विभाग/ दिल्ली सरकार का साथ दे रहे है, को जनता के समक्ष प्रस्तुत करे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग

डॉ. लॉजिस्टिक्स

भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ती गति के साथ, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की मांग में भारी वृद्धि हो रही है। देश के उद्योग जगत में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को रीढ़ माना जा रहा है, और इसे कुशलतापूर्वक संभालने वाले विशेषज्ञों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

वर्तमान समय में, ई-कॉमर्स, विनिर्माण, खुदरा, और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। यह मांग न केवल बड़े महानगरों तक सीमित है, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी यह तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेक्टर में दक्षता बढ़ाने से उत्पादन और वितरण में समय और लागत की बचत हो सकती है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और वैश्विक बाजार में देश की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

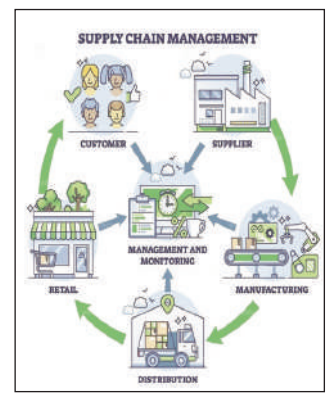

इसके साथ ही, सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं ने भी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के महत्व को बढ़ाया है। विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र इन क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम और प्रमाणन कार्यक्रम पेश कर रहे हैं।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर में योग्य और प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ती है, तो इससे न केवल भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस तरह, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो रही है।

drlogistics.ankur@gmail.com

दिल्ली सरकार बना रही देश का सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो, एलजी और परिवहन मंत्री ने किया शिलान्यास

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार वसंत विहार में देश का सबसे बड़ा मल्टीलेबल इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाने जा रही है। मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और एलजी वीके सक्सेना ने संयुक्त रूप से ई-बस डिपो का शिलान्यास किया।

वसंत विहार के मल्टीलेबल इलेक्ट्रिक बस डिपो में 434 बसें, 230 कार और 200 बाइक्स एक साथ पार्क की जा सकेंगी। 5 एकड़ में फैले और 7.6 लाख वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र के साथ 35 मीटर ऊंचे इस ई-बस डिपो में बेसमेंट के अलावा छह पार्किंग लेवल होगा। यहां सौर पैनल और ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वसंत विहार मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब नहीं होगा, बल्कि यह दिल्ली सरकार की अर्बन मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों और सौर पैनलों से लैस, यह डिपो न केवल आज की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य में भी इस प्रकार के अर्बन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

इस बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस पार्किंग डिपो के निर्माण से इस डिपो की क्षमता 3.5 गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान में यहां 125 बसें पार्क की जाती हैं। लेकिन, इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो के बन जाने के बाद यहां 434 इलेक्ट्रिक बसें पार्क की जा सकेंगी। इसके अलावा यहां 230 कार और 200 बाइक भी पार्क किए जा सकेंगे। यह डिपो 5 एकड़ में होगा। 35 मीटर ऊंचे इस मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का बिल्टअप एरिया 7.6 लाख वर्ग फीट है। वहीं, इसका ग्राउंड कवरेज 1.27 लाख वर्ग फीट है। इस डिपो में एक बेसमेंट और ग्राउंड सहित छह पार्किंग लेवल होंगे।

409.94 करोड़ की लागत से बनने वाले इस डिपो के अगस्त 2026 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस बहुस्तरीय डिपो में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और छत पर 122 केवी का सौर पैनल स्थापित किया गया है। ये सौर पैनल न केवल बसों के लिए छाया प्रदान करेंगे बल्कि 600 किलोवाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेंगे। इसके अतिरिक्त, यहां बसों और सार्वजनिक वाहनों दोनों के लिए 85 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे।

बसों के रखरखाव के लिए डिपो के ग्राउंड लेवल पर 16 बेड पिट होंगे, जो सुव्यवस्थित सर्विसिंग संचालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा बेसमेंट में बाइक और कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। स्थान के अधिकतम उपयोग और यातायात प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए बसों को 45 डिग्री के कोण पर पार्क किया जाएगा। 1:20 की हल्की ढलान वाला 6 मीटर चौड़ा रैंप दो तरफा यातायात को सुचारू बनाएगा, जिससे डिपो के भीतर कुशल आवाजाही सुनिश्चित होगी।

इस डिपो में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी तलों पर पौधे भी होंगे। बहु-स्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो व्यावहारिक कार्यक्षमता के साथ आधुनिक डिजाइन का मिश्रण है। नीचे दिल्ली मेट्रो की लाइन जाने की वजह से और कंपन को कम करने के लिए इसके निर्माण में राफ़्ट पाइलिंग की जगह पाइलिंग फाउंडेशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। बाहरी हिस्से में सभी स्तरों तक आसान पहुंच के लिए परिधि के साथ सावधानीपूर्वक नियोजित रैंप की सुविधा होगी।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के हेड क्वार्टर में बार बार आग लगने की जांच के लिए अमित शाह करे लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के हेड क्वार्टर में बार बार आग लगने की जांच के लिए एक पत्र लिखा।

श्री अमित शाह जी ग्रह मंत्री भारत सरकार को लिखा एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने ग्रह मंत्री जी से शिकायत की कि दिल्ली के परिवहन विभाग के मुख्यालय राजपुर रोड में बार बार आग लगती रहती हैं और कल भी दिनांक 12 अगस्त 2024 को आग लग गई और इसमें काफी फाइल्स और जरूरी कागजात जल के राख़ हों गए.

संजय सम्राट ने पत्र में ग्रह मंत्री को शिकायत करी की दिल्ली के परिवहन विभाग के मुख्यालय में ये आग पेहली बार नहीं लगी हैं इस से पेहले काफी बार आग लग चुकी हैं, इसलिए परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी ने अपना ऑफिस पेहले ही बदल दिया था.

अब ये जांच का विषय हैं की ये आग हर बार अपने आप लगती हैं या किसी साजिश के द्वारा आग लगाई जाती हैं? क्योंकी हर बार आग से जरूरी फ़ाइल और जरूरी दस्तावेज ही जल कर राख हों जाते हैं.

संजय सम्राट का कहना हैं दिल्ली परिवहन विभाग काफी सालो से

बड़े बड़े घोटाले कर चूका हैं जिसमे

स्पीड गवर्नर घोटाला

पेनिक बटन घोटाला

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट घोटाला

10/15 साल पुरानी डीजल /पेट्रोल कार मोटरसाइकिल को घरों से उठाकर प्राइवेट स्क्रैप डीलरो को बेचने का घोटाला.

ऐसे और भी काफी घोटाले हैं जो शायद हमारे संज्ञान में नहीं हैं दिल्ली के परिवहन विभाग में होते रेहते हैं? जिनकी शिकायत हमने समय समय पर ग्रह मंत्री और उप राजयपाल जी को लिखित में दी हैं लेकिन हर बार इन शिकायत को ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया हैं

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने ग्रह मंत्री जी से मांग की हैं की आप दिल्ली के परिवहन विभाग के मुख्यालय में बार बार आग लगने या साजिशना आग लगावने की जांच करवाई जाये.

क्योंकी इस बार बार की आग लगने /लगवाने में भी कोई बहुत बड़ा घोटाला हों सकता हैं इसकी हमें पूरी संभावना लगती हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

संस्कारशाला : सामाजिक कार्यों में सकारात्मक रहने का महत्त्व

डॉ. अंकुर शरण

सामाजिक कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी भी समाजसेवा में शामिल होते हैं, तो हमारी सोच और व्यवहार का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, जिनकी हम मदद कर रहे होते हैं। सामाजिक कार्यों के दौरान मैंने पांच प्रमुख बिंदु सीखे हैं, जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए:

1. धैर्य और सहनशीलता:

सामाजिक कार्यों में सफलता पाने के लिए धैर्य और सहनशीलता बहुत जरूरी है। कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होतीं, और तत्काल परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य रखना और सकारात्मक बने रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं।

2. समर्पण और अनुशासन:

सामाजिक कार्यों में समर्पण और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। जब हम किसी भी काम को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं, तो उसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। यह गुण हमें न केवल काम के प्रति बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति भी प्रतिबद्ध बनाता है।

3. दूसरों की भावनाओं का सम्मान:

सामाजिक कार्य करते समय हमें यह समझना चाहिए कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी समस्याओं को समझकर और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। इससे न केवल उनका विश्वास जीता जा सकता है, बल्कि उन्हें सशक्त भी किया जा सकता है।

4. निरंतर प्रेरणा देना:

सामाजिक कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रेरणा देना जरूरी है। कभी-कभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए होता है। यह प्रेरणा उन्हें मुश्किल हालात से उबरने और आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए, हम अपनी सकारात्मक सोच और अनुभवों को साझा कर सकते हैं।

5. आत्म-निरीक्षण और सुधार:

किसी भी सामाजिक कार्य में अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म-निरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमें बेहतर समाजसेवी बनने में मदद करती है और हमारे काम में सकारात्मक बदलाव लाती है।

सामाजिक कार्यों में सकारात्मक रहना न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे हम समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। जब हम इन पांच प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो न केवल हमें संतोष मिलता है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्य भी सार्थक हो जाते हैं।

"डॉ. अंकुर शरण एक समाजसेवी और ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज के प्रबंधन ट्रस्टी हैं। वे समाज कल्याण और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में सक्रिय हैं, साथ ही पेशेवर दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉ. शरण का मानना है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से बेहतर इंसान बनना और समाज के हित के लिए कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में, सामाजिक और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच सेतु बनाकर, वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।"

सरकारी अडंगा, आतिशी नहीं फहराएगीं तिरंगा

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को लेकर विवाद कम होने की बजाए और बढ गया है ।एलजी के सरकारी अडंगे के चलते आतिशी अब नहीं फहरा सकती तिरंगा झंडा । इस बावत दिल्ली सरकार के विभाग ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्री के निर्देश को लागू करने से मना कर दिया है । दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंत्री गोपाल राय को इस बावत चिट्ठी लिखी है । दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री गोपाल राय को लिखी चिटठी में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है । और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं है ।बता दें कि इस मामले को उपरी स्तर पर संज्ञान में लाया गया गया है और फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है ।दिल्ली जेल नियम के तहत गोपाल राय ने जिस तरह का कम्युनिकेशन दिया है, वो उचित नहीं है । सामान्य प्रशासन विभाग के इस रूख पर आप नेता मनीष सिसौदिया ने बडा ब्यान दिया है ।उन्होने कहा कि दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना से यही उम्मीद कर सकते है । उल्लेखनीय है कि मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को अपने विभाग को निर्देश दिया था कि वह मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर- आए है । उन्होने कहा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर झंडा आतिशी फहराएगीं । इसकी तैयारी की जाए । पर दिल्ली के एलजी ने कानूनी अडंगा लगा दिया है । बता दे कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित आजाद पुर के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीएम झंडा फहराते है ।इस बार सीएम केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से न्यायिक हिरासत में है । दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है ।हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने ऐसा कर कोई दुरभावनापूर्ण काम नहीं किया है ।यही वजह है कि सीएम केजरीवाल झंडा नहीं फहरा सकते ।

प्रशासनिक उदासीनता से जुड़ी गंभीर समस्या: DAV पुलिस पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के पास सड़कों की बदहाल स्थिति

अंकुर शरण

फरीदाबाद के DAV पुलिस पब्लिक स्कूल के पास सड़कों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है । सीवरेज जाम होने के कारण गंदा पानी सड़क पर फैल गया है, जिससे स्कूल परिसर और आस-पास का इलाका कीचड़ और गंदगी से भर गया है । इस गंभीर स्थिति के बावजूद, स्कूल प्रशासन पूरी तरह से असहाय है क्योंकि जाम हुआ सीवरेज नगर निगम फरीदाबाद के अंतर्गत आता है और किसी अज्ञात कारणों से इसे साफ नहीं किया जा सका है ।

इस स्थिति के कारण स्थानीय जनता, खासकर छोटे बच्चों को, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । बच्चे मजबूरन गंदगी और कीचड़ से भरी, फिसलन भरी सड़कों पर चलने को बाध्य हैं, जिससे न केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है ।

इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम के नोडल अधिकारी से विशेष रूप से अपील की जाती है कि वे इस स्थिति को गंभीरता से लें और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करें, ताकि बच्चों और आम जनता को राहत मिल सके ।

स्वच्छता अभियान का संदेश देखकर फेस्टा ने निकाली तरंग यात्रा

सुषमा रानी

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर हर घर तिरंगा हर दुकान तिरंगा के तहत फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सदर बाजार के सैकड़ो व्यापारियों ने कुताब रोड से शुरू होकर मेंन बाजार सदर बाजार से होते हुए 12 टूटी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाल कर सभी को मार्केट को स्वच्छ रखने का संदेश दिया साथ ही उन्होंने सबसे अपील की अपने - अपने घरों के पास पौधे लगाए, पानी को वेस्ट ना करें, रोड़ों पर गंद ना फेक प्लास्टिक थैली का प्रयोग ना करें जैसे जनहित मुद्दों पर आम जनता का जागरूक करने का प्रयास किया । इस अवसर पर सभी भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के जयकारे भी लगा रहे थे । सभी अपने हाथों में तिरंगे लेकर देशभक्ति के गीतों में झूम रहे थे ।

इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने माननीय प्रधानमंत्री से अपील की 15 अगस्त को लाल किला से देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए क्रांतिकारियों को शहीदी का दर्जा देने की घोषणा करें । और सरकार उनके परिवार को सभी सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाई ।

इस इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा, सुरेन्द्र महेन्दू और कमल कुमार ने बताया सदर बाजार की सभी मार्केट को तिरंगे से सजाया जा रहा है ।

इस अवसर पर पवन खंडेलवाल, दीपक मित्तल, सुधीर जैन ने बताया तिरंगा यात्रा को लेकर व्यापारियों में काफी उत्साह था जगह-जगह व्यापारियों ने दुकान से बाहर निकाल कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया ।

वही चौधरी योगेंद्र सिंह, राजकुमार और हरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया बड़ी खुशी की बात है तिरंगा यात्रा में सभी धर्म के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया यही देश की आपसी भाईचारे की मिसाल नजर आती है ।

इस अवसर पर जसविंदर सिंह, वरिंदर सिंह, श्री श्री नारायण गुप्ता, मुकेश कुमार जैन, वरिंदर आर्य, अभय सभरवाल, संदीप खन्ना, कुलदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे ।

क्या डेंगू बुखार के इलाज में मददगार हैं गिलोय, पपीते के पत्ते और बकरी का दूध? जानें एक्सपर्ट की राय

बरसात का मौसम आते ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं । इस दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी कई बीमारियां लोगों को अपना शिकार बनाती हैं । हालांकि, डेंगू (Dengue Fever) इन सभी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है, जिसके मामले देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं । यह एक गंभीर बीमारी है, जो सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से जानलेवा तक साबित हो सकता है । ऐसे में इससे बचाव के साथ-साथ जागरूकता और सही जानकारी (Dengue Health Tips) होना बेहद जरूरी है ।

हालांकि, कई लोग जानकारी के अभाव में इस बीमारी के होने पर सुनी-सुनाई बातों और घरेलू नुस्खों की मदद से इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं । कई लोग डेंगू होने पर गिलोय, पपीते के पत्ते और बकरी के दूध की मदद से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं । ऐसे में आज इस आर्टिकल में मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सीनियर रजिस्ट्रार डॉ. मुजामिल सुलतान से जानेंगे डेंगू में कितना सुरक्षित है गिलोय, पपीते के पत्ते और बकरी के दूध का इस्तेमाल-

पपीते के पत्ते

डॉक्टर के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि डेंगू बुखार के दौरान गिलोय, पपीते के पत्ते और बकरी के दूध का इस्तेमाल कुछ लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन इसे सावधानी से और डॉक्टर की देखरेख में किया जाना चाहिए । डेंगू बुखार के इलाज में प्लेटलेट काउंट एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसे बढ़ाने में पपीते की पत्तियां लाभदायक मानी जाती हैं । इन पत्तियों में मौजूद पपेन और फ्लेवोनोइड्स, प्लेटलेट सिंथसिस और इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ।

हालांकि, इनके असर को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कम है और इनका बहुत ज्यादा सेवन करने से मतली सहित कई नकारात्मक दुष्प्रभाव हो सकते हैं ।

बकरी का दूध

डॉक्टर आगे बताते हैं कि चूंकि बकरी का दूध सेलेनियम जैसे मिनरल से भरपूर होता है, जो इम्युनिटी को मजबूत कर सकता है और गाय के दूध की तुलना में पचाने में आसान होता है, इसलिए अक्सर इसकी सलाह दी जाती है । हालांकि, इसका इस्तेमाल इस बीमारी में देखभाल के एक जरूरी कारक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ।

गिलोय

डॉक्टर कहते हैं कि गिलोय जड़ी-बूटी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रसिद्ध है । ऐसा माना जाता है कि यह शरीर की रक्षा तंत्र का समर्थन करता है और बुखार को कम करने में सहायता करता है । हालांकि, इसका इस्तेमाल भई सीमित ही करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में इसे लेने से लिवर को नुकसान हो सकता है ।

जरूरी बात

अंत में डॉक्टर बताते हैं कि ये हर्बल ट्रीटमेंट सहायक देखभाल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल केयर की जगह नहीं ले सकते । डेंगू बुखार के लिए किसी भी ऑप्शनल ट्रीटमेंट का प्रयास करने से पहले, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें ।

15 अगस्त पर जरूर करें पतंगबाजी, स्ट्रेस दूर करने से लेकर वेट लॉस में भी मिलेगी मदद

भारत इस साल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है । इस मौके पर बच्चों से लेकर बड़ों तक कई लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं । इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि ये महज एक शौक ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी हेल्दी एक्सरसाइज है । इससे होने वाले फायदे जानकर आप भी खुद को पतंग उड़ाने (Kite Flying On Independence Day) से रोक नहीं पाएंगे ।

नईदिल्ली । 15 अगस्त पर आसमान में ढेर सारी रंग-बिरंगी पतंगे दिखाई देती हैं । आजादी का यह खास दिन लोग कई तरह से मनाना पसंद करते हैं, जिनमें से पतंग उड़ाना भी एक है । चाहे बच्चे हों या फिर बड़े, हर कोई इस दिन के लिए पहले से ढेर सारी पतंग खरीदकर रख लेता है, अगर आप भी इनमें से एक हैं तो अब खुश हो जाइए । जी हां, आज हम आपको पतंग उड़ाने से जुड़े कुछ शानदार फायदों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो हर किसी को जान लेने चाहिए । इसके बाद जो कोई भी आपको पतंग उड़ाने से रोके, उसके साथ आप इस आर्टिकल का लिंक शेयर कर सकते हैं ।

वेट लॉस में मददगार

आपको जानकर हैरानी होगी कि पतंग उड़ाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है । ऐसे में, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो 15 अगस्त के इस खास मौके पर आलस को किनारे रखकर दिल खोलकर पतंगबाजी कर सकते हैं । पतंग उड़ाते वक्त आपकी मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं, जिससे पूरे शरीर की बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है ।

मिलता है भरपूर विटामिन डी

पतंग उड़ाने के लिए आपको मजबूरन सूरज की रोशनी में खड़ा होना पड़ता है, ऐसे में आपका यह शौक शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कराने में भी मदद करता है । इसलिए आपको भी बेझिझक खुले आसमान के नीचे पतंग उड़ानी चाहिए ।

फोकस बढ़ाने में फायदेमंद

पतंग उड़ाने में काफी एकाग्रता (Focus) की जरूरत होती है । ऐसे में, ध्यान को भटकने से रोकने में भी यह एक बढ़िया एक्सरसाइज साबित होती है । 15 अगस्त के अलावा भी अगर आप रोजाना कुछ समय के लिए पतंग उड़ाते हैं तो इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह खासतौर से फायदेमंद है ।

दूर होता है स्ट्रेस

पतंग उड़ाने का शौक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है । इससे चिंता और तनाव से छुटकारा मिलता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस मजेदार एक्सपीरिएंस को एन्जॉय करने में होता है । यकीन न हो, तो आप पतंग उड़ा रहे शख्स को थोड़ा गौर से देखें और आप पाएंगे कि वह दुनियादारी की परवाह किए बगैर अपनी धुन में खोया हुआ है ।

फेफड़ों को रखे हेल्दी

पतंग उड़ाने से आपके फेफड़े भी हेल्दी रहते हैं । इस दौरान आपका मुंह आसमान यानी ऊपर की ओर होता है, जिससे एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है और शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति भी हो जाती है ।

77वां या 78वां? 2024 में कौन-सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा भारत, दूर करें कन्फ्यूजन

इस साल देश आजादी के जश्न का 77वां साल मना रहा है या फिर 78वां? अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि इस साल भारत कौन-सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो यहां आप मिनटों में इस सवाल का सही जवाब पा सकते हैं । हम आपको इसका कैलकुलेशन भी समझाएंगे कि आखिर किस तरह आप खुद भी इसे चेक कर सकते हैं ।

नई दिल्ली । साल 1947 में 15 अगस्त के दिन ब्रिट्रिश हुकूमत से मिली आजादी को देश हर साल सेलिब्रेट करता है, लेकिन कई लोग इन दिनों इस बात को लेकर कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं कि भारत इस साल यानी 2024 में कौन-सा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है । कुछ इसे 77वीं, तो कई लोग इसे आजादी की 78वीं वर्षगांठ बता रहे हैं । आइए फटाफट जान लीजिए इस सवाल का सही जवाब ।

कन्फ्यूजन में हैं लोग

अगर स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को लेकर आपको भी कन्फ्यूजन है तो इस आर्टिकल में सबकुछ एकदम क्लियर हो जाएगा । 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी । तभी से हर साल इस ऐतिहासिक दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है । बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब लोगों के मन में इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा हुई है । आइए जानें कि भारत इस साल कौन-सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है यानी हमें अंग्रेजों से आजादी मिले कितने साल बीत गए हैं ?

77वां या 78वां स्वतंत्रता दिवस ?

आजादी के जश्न की शुरुआत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराकर की थी । अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि हम कौन-सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो बता दें कि अगर आजादी की वास्तविक तारीख (15 अगस्त 1947) से गिनें तो आजादी के पहले वर्ष को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद किया जाता है । ऐसे में, इस साल भारत आजादी के 77 वर्ष पूरा कर लेगा, तो इसे 78वां स्वतंत्रता दिवस माना जाएगा ।

महिला को दे सकती है बीजेपी अध्यक्ष की कमान?

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तलाशने में जुटी है। दरअसल बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन में चल रहे है। अभी तक नए अध्यक्ष के नाम पर हाथ खाली है। खबरों के मुताबिक अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा की हाई लेवल बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे।सूत्रो की माने तो बीजेपी पार्टी की हाईकमान (ओबीसी) यानि अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी महिला नेता के हाथों में भी जा सकती है।फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बता दें कि सूत्रो के हवाले से मालूम हुआ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर लंबी बैठक चली। करीब 5 घंटे तक लंबी चली बैठक के दौरान

नए अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया।बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महासचिव बी एल संतोष,संघ कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले,और संयुक्त सह कार्यवाहक अरूण कुमार शामिल थे। अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक अगले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संघ की तरफ से सहमति मिलना जरूरी। दरअसल पार्टी में पहले ही अहम पदो पर रह चुके दिग्गजों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा चुका है।तो भाजपा और संघ के पदाधिकारी जमीनी राजनीति के बैकग्राउंड वाले नेता की तलाश में जुटे है। रिपोर्ट के मुताबिक अटकलें है कि अगला अध्यक्ष महिला या ओबीसी भी हो सकता है।इससे पहले कभी भी भाजपा की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं रही। क्यास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष की दौड में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का नाम भी खासा चर्चा में है। हालांकि फडणवीस या भाजपा की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनके नाम को लेकर अटकलें और तेज हो गई थी।

"भाजपा बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी 'आप' टूटी नहीं, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आये और सच्चाई की जीत हुई"

सुषमा रानी

नई दिल्ली। तानाशाही के ख़िलाफ़ सच्चाई की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने अपने नए डीपी कैंपेन 'सत्यमेव जयते' की शुरुआत की है। मंगलवार को वरिष्ठ आप नेता आतिशी ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसकी घोषणा की। कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी के सभी नेता-कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलेंगे।

इस मौक़े पर वरिष्ठ 'आप' नेता आतिशी ने कहा कि, पिछले 2 साल भाजपा की केंद्र सरकार ने, उनकी तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए, रेड की लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार का एक रुपया भी नहीं मिला।

लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार किया, सतेंद्र जैन को गिरफ़्तार किया, संजय सिंह को गिरफ़्तार किया, दिल्ली के

लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया। ऐसी गिरफ़्तारियाँ स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है।

उन्होंने कहा कि, उस समय भी जो लोग अंग्रेजों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, उनको भी झूठे मुक़दमों के तहत जेल में डाला जाता था। जवाहर लाल नेहरू जेल रहे, लाला लाजपत राय जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे।

आप नेता आतिशी ने कहा कि, हर तानाशाह अपने विरोधियों को अपने विपक्षियों को चुप करने के लिए जेल में डालने की कोशिश करता है। भाजपा ने भी सोचा था कि, अपनी तानाशाही से आम आदमी पार्टी को दबा देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन उनकी हर संभव कोशिश के बाद भी आम आदमी पार्टी नहीं टूटी। और आख़िरकार मनीष सिसोदिया के जेल में 17 महीने रहने के बाद सच्चाई की जीत हुई और मनीष सिसोदिया जी बाहर आए।

उन्होंने कहा कि, आज इस सच्चाई की जीत के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी 'सत्यमेव जयते' का डीपी कैंपेन शुरू कर रही है। आम आदमी पार्टी के सभी सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते के डीपी कैंपेन की शुरुआत हो रही है।

आप नेता आतिशी ने कहा कि, हम भाजपा को ये बताना चाहते है कि वो हमें कितना भी परेशान कर ले लेकिन तोड़ नहीं सकते है। वो चाहे कितने समय भी हमारे नेताओं में जेल में डाल दे लेकिन जीत आख़िरकार सच्चाई की ही होगी।

उन्होंने साझा करते हुए कहा कि, आज दोपहर 3 बजे से आम आदमी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और सोशल मीडिया हैंडल सत्यमेव जयते के डिसप्ले पिक्चर को कैंपेन के रूप में शुरू करेंगे।

ओल्ड रेलवे ब्रिज पर अभी पानी का स्तर 204.35 मापा गया है, जो की वार्निंग लेवल के करीब है सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

नई दिल्ली, यमुना में बढ़ते जल स्तर के चलते दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों संग यमुना की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया I निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय डीएम और एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे I मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अभी यमुना मे जल स्तर 204.35 पर है, जो की वार्निंग लेवल के लगभग आसपास है I उन्होंने बताया कि अभी किसी प्रकार के खतरे की कोई आशंका नहीं है I

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हथिनी कुंड बैराज की ओर से लगभग 13000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना में जल स्तर बढ़ने की आशंका है I इसी संदर्भ में आज मंत्री सौरभ भारद्वाज यमुना में जल स्तर का और वर्तमान स्थिति का जायजा लेने पहुंचे I उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान उनके साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के आला अधिकारी, राजस्व विभाग के आला अधिकारी एवं क्षेत्र के डीएम और एसडीएम भी मौजूद रहे I उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा सभी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं I पानी की बोट, मुनादी का सामान तथा अन्य बाकी सभी जरूरी इंतजाम दुरुस्त कर लिए गए हैं I उन्होंने बताया की फिलहाल अभी किसी प्रकार के खतरे की कोई बात नहीं है, अभी सभी परिस्थितियों नियंत्रण में है I

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को यमुना से दूर रहने एवं एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं I उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, कि जलस्तर बढ़ने पर यमुना के आसपास रहने वाले लोगों के बच्चे पानी में नहाने और मौज मस्ती करने आ जाते हैं, जिसके कारण अक्सर हादसे हो जाते हैं I इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए लोगों को निर्देश जारी किए गए हैं, कि वह यमुना से दूर रहें और इतिहास बरते I उन्होंने बताया हालांकि अभी यमुना के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि पानी अभी वार्निंग लेवल के स्तर तक भी नहीं पहुंचा है, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए एहतियात

बरतना बेहद जरूरी है I

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना में जल स्तर की वर्तमान स्थिति की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करते हुए बताया, कि अभी यमुना स्थित ओल्ड रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मापा गया है, जो कि वार्निंग लेवल के लगभग नजदीक है, परंतु अभी वार्निंग लेवल तक पहुंचा नहीं है I उन्होंने कहा कि हथिनी कुंड बैराज की ओर से लगभग 13000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो हमें ऐसी उम्मीद है, कि जल्द ही यह स्तर वार्निंग लेवल तक पहुंच सकता है I इसी के चलते आज यह दौरा किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के सभी पुख्ता इंतजाम दुरुस्त कर लिए जाएं I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दौरा करने के पश्चात जो स्थिति निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक विभाग के द्वारा सभी उपयुक्त इंतजाम कर लिए गए हैं और अभी किसी भी प्रकार से घबराने की कोई बात नहीं है I उन्होंने कहा कि अभी सभी परिस्थितियां नियंत्रण में है I

यमुना में बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, कि विभाग के द्वारा मानसून आने से पहले ही यमुना के बीच-बीच में बने मिट्टी के टापू के बीच में पायलट कट लगाए गए थे, जो कि इस बार मानसून आने पर बेहद ही कारगर सिद्ध हुए हैं I उन्होंने बताया इन टापू के बीच में बनाए गए पायलट कट के माध्यम से पानी आसानी से बेहतर निकल रहा है और साथ ही साथ जो टापू सालों से धीरे-धीरे जम रही मिट्टी के कारण बन गए थे, जो कि पानी यमुना से बाहर निकल जाने का एक बड़ा कारण होते थे, वह सभी टापू भी पानी के बहाव के साथ बेहकर निकल गए I वर्तमान स्थिति में यमुना का पानी आसानी से बेहकर आगे निकल जा रहा है I उन्होंने कहा की वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखकर हम यह उम्मीद कर सकते हैं, कि यदि यमुना में पानी का स्तर बढ़ा भी तो यमुना के आसपास के क्षेत्र में इस बार पानी भरने की समस्या नहीं होगी I

बढ़ते जल स्तर को लेकर यमुना के किनारे बसे लोगों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि जब कभी जमुना में जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है या खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है तो यमुना के आसपास के क्षेत्र में बसे लोगों को विस्थापन कर उन्हें ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट कर दिया जाता है I सरकार द्वारा उनके लिए रहने खाने और दवाइयां के सभी इंतजाम किए जाते हैं I उन्होंने कहा परंतु अभी यमुना में इस प्रकार की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही की यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जाए, परंतु यदि इस प्रकार की कोई स्थिति बनती भी है, तो विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

लोगों को घायल होने से और पक्षियों की जान बचाने के लिए चाइनीज मांझा इस्तेमाल न करने की दिलाई शपथ

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 15 अगस्त नजदीक आते-आते पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है इन पतंगों को उड़ाने के लिए कई बार लोग चाइनीज मांजे का इस्तेमाल करते हैं परिणाम स्वरूप आसमान में उड़ने वाले पक्षी इस मांजे से घायल हो जाते हैं कई बार बाइक सवार भी इस मांजे की चपेट में आ जाते हैं इसी के चलते हर साल की तरह इस साल योगेन्द्र कुमार मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि AWBI एवं हैड वार्डर तिहाड जेल एवम् पेटा इण्डिया ने मिलकर चाइनीज माँझे के विरुद्ध अभियान के तहत राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय अशोक नगर तथा राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय रमेश नगर नई दिल्ली के विद्यार्थियों के बीज "चाइनीज माँझे के दुष्प्रभाव" विषय पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, इस अवसर पर योगेंद्र कुमार ने बच्चों बताया कि हर साल लगभग 1000 पक्षियों की जान इस चाइनीज के कारण चली जाती और सैकड़ों लोग भी घायल हो जाते है, पिछले पांच साल में 14 लोगों ने अपनी जान गवाई, ओर योगेंद्र ने

2400 सौ बच्चों को चाइनीज मांझा इस्तेमाल ना करने के लिए शपथ भी दिलवाई, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश एवम् सफी मोहम्मद ने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि चाइनीज माँझे का इस्तेमाल ना करे, ओर कोई भी इसका इस्तेमाल करे तो उसे भी इस्तेमाल ना करने के लिए प्रेरित करे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर संदीप ने भी चाइनीज माझा इस्तेमाल ना करने के लिए अपील की, इस अवसर में बी के पांडे, इंदर सोनी मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि AWBI तथा अनिल चौधरी, देविंदर मखीजा, सोनू, राम निवास यादव, जोगेन्दर कुमार जय नाथ एनिमल केअर टेकर ने भी बच्चो को चाइनीज मांझा इस्तेमाल ना करने की अपील की।

एक चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण : मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के मुद्दे पर साझा करते हुए वरिष्ठ 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि, स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर दिल्ली में चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने से रोकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि, तिहाड़ से महाठग सुकेश की चिट्ठी तुरंत एलजी साहब के पास पहुँच जाती है और वो इसपर एक्शन भी लेते है लेकिन उनतक चुने हुए मुख्यमंत्री की चिट्ठी नहीं पहुँचती है। जिस एलजी साहब को महाठग सुकेश की चिट्ठियों से इतना प्यार है कि उसके एक-एक शब्द को सच मानते हैं; उन एलजी साहब को एक बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की चिट्ठी को भी तिहाड़ से मँगवा लेना चाहिए।

इस विषय में साझा करते हुए वरिष्ठ आप नेता आतिशी ने भी कहा कि, ₹आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार की छीना जा रहा है। आज दिल्ली में एक नए वायसराय आ गये है जो कह रहे है कि झंडा वो फहरायेंगे। 15 अगस्त को तिरंगा फहराना देश के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों को अधिकार है, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है। अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिया जाता तो तानाशाही का इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि, हम 15 अगस्त को तिरंगा इसलिए फहराते है क्योंकि 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब भारत के लोगों को ख़ुद पर राज करने का अधिकार मिला। इससे पहले भारत में अंग्रेजों का राज होता था, जो भारत में एक वायसराय को भेजते थे और वो मनमर्ज़ी से अपनी सरकार चलाता था। उस सरकार में भारत के लोगों का कोई अधिकार नहीं होता था।

आप नेता आतिशी ने कहा कि, हम 15 अगस्त को तिरंगा लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए, भारत के लोगों के हक़ की आवाज़ के लिए फहराते है। लेकिन आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार की छीना जा रहा है। आज मानो दिल्ली में एक नए वायसराय आ गये है जो कह रहे है कि झंडा वो फहरायेंगे।

उन्होंने कहा कि, "मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि, 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना है और वो तिरंगा फहराना देश के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों को अधिकार है और दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है।और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिया जाता तो तानाशाही का इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं होगा। हम देखेंगे

कि भाजपा तानाशाही के साथ खड़ी है या फिर लोकतंत्र के साथ खड़ी है।"

आतिशी ने कहा कि, तिरंगा चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री फहराते है। लेकिन झूठे केस में न्यायिक हिरासत के होने के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी इच्छा ज़ाहिर कर उनकी जगह मुझे बतौर मंत्री झंडा फहराने की अनुमति दी है।

इस बाबत उन्होंने तिहाड़ जेल से एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। लेकिन वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब के पास पहुँचती है। जिस चिट्ठी के आधार पर एलजी साहब सीबीआई जाँच के आदेश भी दे देते है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की चिट्ठी जब एलजी साहब के पास जाती है तो अफ़सरों से कहलवाया जाता है कि केवल नीति चिट्ठियाँ ही जेल से बाहर जा सकती है कोई ऑफिसियल लेटर नहीं। ये क़ानून तो सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल के लिए है, सुकेश चन्द्रशेखर के लिए नहीं।

उन्होंने साझा करते हुए कहा कि, इसके बार गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल से मिलने जाते है। गोपाल राय बतौर जीएडी मंत्री अधिकारियों को आदेश देते है कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इच्छा है कि, उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराए। उसके जबाव में भी अफ़सरों से कहलवाया जाता है कि, वो इस आदेश की नहीं मानेंगे।

आतिशी ने कहा कि, एलजी अंग्रेजों के राज की तरह एक नए वायसराय के रूप में दिल्ली के लोगों की इच्छा, उनकी चुनी हुई सरकार की इच्छा के ख़िलाफ़ सरकार चलाने की कोशिश कर रहे है, चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के हक़ को छीनने की कोशिश कर रहे है और इस सबसे तानाशाही की बू आती है।

आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी साझा करते हुए कहा कि, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर घटिया राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि, एक तरफ़ जेल में बंद महाठग सुकेश चन्द्रशेखर है, उसकी चिट्ठी तिहाड़ प्रशासन एलजी साहब को भेजता है और एलजी भी बाक़ायदा उसपर एक्शन लेते है।

वरिष्ठ आप नेता ने आगे कहा कि जब दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते है तो एलजी साब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं कि, ख़बरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री का लिखा पत्र न भेजा जाये लेकिन जब सुकेश पत्र लिखता है तो पूरा एलजी कार्यालय इंतजार करता होगा कि, 'हर पल भारी पड़ रहा है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहां है'? जिन एलजी साब को सुकेश के पत्र से इतना प्यार है और उसके एक-एक शब्द को सच मानते हैं, उन एलजी साब को एक बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी को भी मँगवा लेना चाहिए था।

मनीष सिसौदिया ने कहा की, "स्वतंत्रता दिवस एक पावन मौक़ा है, अगर दिल्ली के एक मौजूदा सीएम ने इसके बारे में पत्र लिखा है, तो एलजी साब के कार्यालय को डीजी कार्यालय में फोन करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि सीएम अरविंद की लिखी चिट्ठी कहाँ है? उन्हें यह चिट्ठी माँगनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें न तो आजादी की चिंता है और न ही देश की, उन्हें बस सुकेश जैसे लोगों की चिंता हैं।"

महिलाए भी पोस्को के दायरे में चलेगा मुकदमा:हाई कोर्ट

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को भी बच्चे पर प्रिवेंशन लैंगिक हमले के लिए यौन अपराधो से बच्चों का संरक्षण (POSCO) एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड सकता है।और इस अपराध के लिए अदालती कार्यवाही केवल पुरूषो तक ही सीमित नहीं है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि पोस्को अधिनियम बच्चो को यौन अपराध से बचाने के लिए बनाया गया था कि चाहे अपराध किसी पुरूष द्वारा किया गया हो या महिला द्वारा। जस्टिस भंभानी ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि धारा-3 (प्रिवेंशन लैंगिक हमला) में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति को केवल पुरूष के संदर्भ में पढा जाए। दरअसल अदालत का यह फैसला बीते हफ्ते पास्को मामले में एक आरोपी की याचिका पर आया था।जिसमें दलील दी गई थी कि चूकि वह एक महिला है।इसलिए इसके खिलाफ प्रिवेंशन लैंगिक हमला के अपराध में मुकदमा नहीं

चलाया जा सकता। आरोपी ने अपने खिलाफ आरोप तय करने पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि प्रावधान को पढने से पता चलता है कि इसमें पुरूष संबोधन के लिए बार-बार सर्वनाम 'वह' का इस्तेमाल किया गया है,जिसका मतलब है कि विधायिका का इरादा केवल पुरूष अपराधी के खिलाफ कार्रवाही से था।

हालांकि अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कारण नही है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा -3 में उल्लेखित व्यक्ति शब्द को केवल पुरूष के संदर्भ में पढा जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा ,इसके अनुसार यह माना जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 5 (गंभीर प्रिवेंशन लैंगिग हमला) में उल्लेखित कृत्य अपराधी की लैंगिग स्थिति की परवाह किए बिना अपराध है।बशर्ते किसी बच्चे पर किए गए हो।

दिल्ली ब्रिगेड ने हृदय संबंधी आपातकालीन प्रतिक्रिया पर एक विशेष सत्र आयोजित किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। COVID-19 के लंबे समय तक प्रभाव के कारण, कई लोग दीर्घकालिक लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, जो गंभीर हृदयाघात से अधिक संख्या में मौतें हो सकती हैं, विशेषकर युवाओं में जनसंख्या ज्यादा है। जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को शिक्षित करने के प्रयास में कि इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे दी जाए आपातकालीन स्थिति में, दिल्ली ब्रिगेड ने हृदय संबंधी आपातकालीन प्रतिक्रिया पर एक विशेष सत्र आयोजित किया और हरकेश नगर में सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आई डी 1925341 में 12 अगस्त 2024 को तत्काल कार्रवाई, सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। प्राथमिक मूल्यांकन, और चरण-दर-चरण प्रक्रियाएँ, और इसमें सीपीआर का प्रदर्शन शामिल था।

इस सत्र में तीन शिक्षक एवं 200 छात्राओं ने भाग लिया, जबकि विद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य प्रबंधन समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। सत्र सुबह 9:00 बजे से आयोजित किया गया था आगे और लगभग तीन घंटे तक जारी रहा। सत्र के अंत में, प्रतिभागी थे प्रभावी सीपीआर के लिए प्रश्न पूछने और सही तकनीकों के साथ डमी पर अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया परिणाम. प्रतिभागियों ने किसी हताहत को संभालने और स्थानांतरित करने के कौशल का भी अभ्यास किया। यह सत्र था छात्रों और शिक्षकों की उत्साहपूर्ण बातचीत और प्रतिक्रियाओं के साथ संपन्न हुआ।

सहायक आयुक्त श्री पी डी वेरखिया के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व और दक्षिण जिलों की दिल्ली ब्रिगेड टीम।, कोर कमांडर (एन) सुश्री मोनिका, और कोर कमांडर श्री श्याम, संगठित और टीम के अन्य सदस्यों के साथ एक सत्र आयोजित किया। स्कूल अधिकारियों ने सत्र की सराहना की और इसे और अधिक स्कूलों तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि यह बचत के लिए एक मूल्यवान सीखने का अनुभव है ज़िंदगियाँ। दिल्ली ब्रिगेड सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस जागरूकता को फैलाने के लिए समर्पित है जीएनसीटी दिल्ली, क्योंकि यह समय की मांग है। क्रप्या अपने सुझाव हमे ईमेल stjohnambulancedelhi@yahoo.com पर प्रेषित करें व अपने स्कुल कॉलेज कार्यालय आदि में भी करवाने के लिये रिक्वेस्ट भेजें। अतिरिक्त आयुक्त पी के राणा St John Ambulance Brigade Delhi.

सीएम योगी 24 अगस्त को करेंगे टेक्नीशियन वर्ल्ड कप का शुभारंभ, 46 देश के खिलाड़ी होंगे शामिल

यूपी के नोएडा में रोबोटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इस टेक्नीशियन वर्ल्ड कप का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस चैंपियनशिप में 46 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। बताया गया कि प्रतियोगिताएं 14 श्रेणियों में होंगी जिनमें स्वायत्त रोबोटिक्स ड्रोन रेसिंग और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। इनमें कुल 50 लाख रुपये के पुरस्कार होंगे।

ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अगस्त को सेक्टर 21 स्थित नोएडा स्टेडियम में टेक्नीशियन वर्ल्ड कप 2024 का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि 27 अगस्त तक होने वाली इस रोबोटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। 46 देशों से प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फार रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (एआइसीआरए) के सहयोग से मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है।

यह भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड होगा

एआईसीआरए के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया कि आयोजन के आठवें संस्करण में 46 देश की 2,500 से अधिक टीमें भाग लेंगी, जिसमें 12 हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। यह भागीदारी का विश्व रिकॉर्ड होगा।

14 श्रेणियों में होंगी प्रतियोगिताएं

बताया गया कि प्रतियोगिताएं 14 श्रेणियों में होंगी, जिनमें स्वायत्त रोबोटिक्स, ड्रोन रेसिंग और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं, जिनमें कुल 50 लाख रुपये के पुरस्कार होंगे।

इसमें ब्राजील, कनाडा, मिस्र, जर्मनी, ईरान, इराक, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, नार्वे, पैराग्वे, फिलीपींस, प्यूर्टो रिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया, तुर्किये, अमेरिका, यूएई समेत 46 देश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

चैंपियनशिप में रोबो फुटबाल, रोबो रेस, बाट्स काम्बैट, मेज साल्वर, ड्रोन रेस, आरसी प्लेन, वाटर राकेट, सूमो बाट, ड्रोन फुटबाल, एफपीसी ड्रोन रेसिंग, आरसी इलेक्ट्रिक कार रेसिंग, रोबो हाकी, फास्टेस्ट लाइन फालोअर और इनोवेशन प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतिभागियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से जुड़ने और रोबोटिक्स व आटोमेशन पर वैश्विक चर्चा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

नोएडा एयरपोर्ट होगा और बड़ा, एयरपोर्ट बना रही कंपनी ने दिया नया मास्टर प्लान; यात्रियों की आवाजाही होगी आसान

परिवहन विशेष न्यूज

अगर विस्तारित मास्टर प्लान को स्वीकृति मिलती है तो दोनों रनवे की बीच की दूरी 2400 मीटर हो जाएगी। इससे ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को दी गई जमीन 1334 हे. में और क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। नियाल ने एमआरओ के लिए 1365 हे. जमीन का अधिग्रहण किया है। इस जमीन पर एमआरओ के अलावा एक रनवे बनाया जाएगा। इसलिए जमीन की कोई अड़चन नहीं होगी।

ग्रेटर नोएडा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़ा होगा। एयरपोर्ट का निर्माण कर रही विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने एयरपोर्ट का विस्तारित मास्टर प्लान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नियाल) को दिया है।

टर्मिनल की आपस में कनेक्टिविटी व रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी के लिए रनवे के बीच दूरी बढ़ाने को विस्तारित मास्टर प्लान दिया गया है। नियाल ने इसके अध्ययन की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूसी को दी है। इसके बाद यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। जेवर में 1334 हेक्टेयर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है।

दोनों रनवे के बीच 1600 मीटर की होगी दूरी

दिसंबर में एक रनवे के साथ एयरपोर्ट का संचालन शुरू होगा। एयरपोर्ट के लिए सड़क से लेकर रेल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। यात्रियों की सालाना संख्या एक करोड़ बीस लाख होने पर दूसरे रनवे का निर्माण शुरू होगा।

दोनों रनवे के बीच 1600 मीटर की दूरी होगी, लेकिन विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने नियाल को विस्तारित मास्टर प्लान सौंपकर रनवे की बीच की दूरी बढ़ाने की मांग की है।

रनवे के बीच की दूरी बढ़ाने की जरूरत

एयरपोर्ट की विस्तरित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए देश व दुनिया के कई एयरपोर्ट का अध्ययन किया गया था। इसके मुताबिक ही दोनों रनवे की दूरी को 1600 तय किया गया था। लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डर में ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर बनाकर रेल, नमो भारत रेल, सड़क आदि से कनेक्टिविटी का विचार नहीं था।

अब इन परियोजनाओं पर काम हो रहा है। भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार छह रनवे तक करने की योजना है। इसके लिए टर्मिनल बिल्डिंगों को भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ताकि यात्रियों को आवाजाही में आसानी हो। इसलिए रनवे की बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए विस्तारित मास्टर प्लान दिया गया है।

तीसरे चरण में 2082 हे. के जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव

नियाल ने एयरपोर्ट के लिए आरक्षित जमीन का पूरी तरह से अधिग्रहण करने के लिए तीसरे चरण में 2082 हे. का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज रखा है। इस पर एसआइए की प्रक्रिया चल रही है। तीनों चरण में कुल 4781 हे. जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा।

विस्तारित मास्टर प्लान स्वीकृति होने की स्थिति में इस क्षेत्रफल में छह के बजाए पांच रनवे का ही निर्माण हो सकेगा। छह रनवे के निर्माण के लिए मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृति मिलते ही करीब एक हजार हेक्टेयर और जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया है।

इसके अधिग्रहण से अलीगढ़ जिले के टप्पल की सीमा तक एविएशन हब की सीमा पहुंच जाएगी। यमुना प्राधिकरण पहले ही इस क्षेत्र को एविएशन हब में शामिल करने का प्रस्ताव बोर्ड से स्वीकृत करा चुका है।

चार एयरलाइंस कंपनी की शुरू होगी सेवा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चार एयरलाइंस कंपनी की यात्री सेवाएं उपलब्ध होगी। इसमें एयरइंडिया, अकासा, इंडिगो व स्पाइस जेट शामिल हैं। इन कंपनियों के विमान भी नोएडा एयरपोर्ट के हैंगर में खड़े होंगे।

नोएडा एयरपोर्ट का विस्तारित मास्टर प्लान विकासकर्ता की ओर से दिया गया है। रनवे की बीच की दूरी को बढ़ाकर 2400 मीटर करने का प्रस्ताव है। तुर्किये के इस्तांबुल व चीन के बीजिंग में बनाए जा रहे एयरपोर्ट पर रनवे के बीच की दूरी 2400 है।

कनेक्टिविटी के लिए रनवे के बीच की दूरी बढ़ाने की जरूरत है। विस्तारित मास्टर प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। -डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ नियाल

सही जगह होता यूनीपोल का बेस तो न बुझता दो घरों का चिराग! नियम का नहीं हुआ पालन

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद यूनीपोल के बेस का मुद्दा गरमा गया है। यूनीपोल का गलत बेस 10 साल से बना है। इस पर न तो यातायात पुलिस का ध्यान जा रहा है और न ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का। आइएसटीएमएस के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि एचटीएमएस के जरिए यूनीपोल तैयार कराए गए थे। पांच यूनीपोल का प्रयोग यातायात पुलिस कर रही है।

नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर मयूर स्कूल के पास लगे यूनीपोल (ग्रेंटी) के जरिये यातायात पुलिस सुरक्षित सफर के लिए राहगीरों को जागरूक करती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटती है, लेकिन इस यूनीपोल का बेस ही गलत बना है। नियमानुसार इसका बेस क्रैश बैरियर के बाद बनना था, लेकिन यहां पर उसके पहले बना है। उसमें कार की जोरदार टकर होने से सोमवार को दो सगे भाईयों सहित तीन युवाओं की जान चली गई। यदि यूनीपोल का बेस नियमानुसार बना होता तो शायद दो घरों का चिराग न बुझता।

यूनीपोल से पुलिस करती है लोगों को जागरूक

हाईवे पर लगाए गए यूनीपोल से यातायात पुलिस लोगों में जागरूकता फैलाती है। लोगों को सुरक्षित सफर के लिए नियमों का पालन कराने का पाठ पढ़ाती है।

जैसे-लेन में ड्राइविंग करें, नशे में वाहन न चलाएं, वाहन को ओवरस्पीड में न चलाएं, ओवरटेक दायीं ओर से करें आदि।

यातायात पुलिस ने 10 वर्ष पहले नोएडा प्राधिकरण के नोएडा ट्रैफिक सेल (एनटीसी) के माध्यम से हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एचटीएमएस) योजना लॉन्च कराई थी, जिसमें माध्यम से ई-चालान की सुविधा शुरू की गई।

अब यह मॉडिफाई होकर इंट्रीग्रेटेड सिक्योर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसटीएमएस) में तब्दील हो चुकी है। यातायात पुलिस की ओर से सुरक्षित सफर के लिए इन्हीं यूनीपोलों पर कैमरों को लगाकर ई-चालान व मॉनिटरिंग का काम सेक्टर-94 स्थित कमांड कंट्रोल रूम से किया जा रहा है।

हाईवे के किनारे क्रैश बैरियर भी लगाए गए हैं। इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक कोई जानवर या व्यक्ति अचानक हाईवे पर न आने पाए। दूसरा यदि कोई वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे जाए तो वह क्रैश बैरियर से टकराकर रुक जाए। वाहन चालाकों को गंभीर चोट न आए।

ड्रेन की वजह से तो आगे नहीं लगाया

मयूर स्कूल के पास हाईवे के किनारे क्रैश बैरियर के बाद ड्रेन है। माना जा रहा है कि इस वजह से ही यहां यूनीपोल का बेस क्रैश बैरियर के बाद न बनाकर पहले बना दिया गया है।

लोगों का कहना है कि यदि यूनीपोल का बेस नियमानुसार क्रश बैरियर के बाद बना होता तो कार पहले उससे टकराती। इससे कार सिर्फ क्षतिग्रस्त होती या तीन युवा सिर्फ घायल होते। यूनीपोल का बेस कंक्रीट से काफी मजबूती से बना है। उससे सीधे कार टकराने से तीनों की जान चली गई।

अधिकारी बने अनजान

यूनीपोल का गलत बेस 10 साल से बना है। इस पर न तो यातायात पुलिस का ध्यान जा रहा है और न ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का। आइएसटीएमएस के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि एचटीएमएस के जरिए यूनीपोल तैयार कराए गए थे। पांच यूनीपोल का प्रयोग यातायात पुलिस कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर सिविल डिफेंस मथुरा ने ली बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा: दिनांक 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार को शाम 4 बजे नागरिक सुरक्षा मथुरा के उप नियंत्रक जसवंत सिंह के द्वारा स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में नागरिक सुरक्षा मथुरा कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी स्वतंत्रता दिवस, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रोस कंट्री दौड़ का आयोजन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शांति व्यवस्था बनाने में ड्युटी को लेकर अधिकाधिक श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा व यातायात व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश दिए। साथ ही

श्रद्धालुओं से विनम्र रहे तथा ड्यूटी का जिम्मेदारी से निर्वहन करने को लेकर बैठक आयोजित की गई साथ ही जिसमें नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के उप नियंत्रक जसवंत सिंह सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह, डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी डिप्टी डिविजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल, घटना नियंत्रक अधिकारी सचिन अग्रवाल, पोस्ट वार्डन अशोक यादव, महेश शर्म, सैक्टर वार्डन शुभम-कुमार, जितेन्द्र धनगर, गोपाल चतुर्वेदी, सैलेश खंडेलवाल, सुनैना गुप्ता, आलोक व्यास, राकेश, रिंकी यादव, जवर सिंह, जीवन दीप कल्याण आदि बैठक में मौजूद रहे।

मालदीव-भारत के बेहतर होते रिश्तों के सबब

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकाट मालदीव ट्रेंड होने लगा। इस हैशटैग के साथ लोगों के ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिसमें वे मालदीप और लक्षद्वीप की तुलना करते हुए लक्षद्वीप को बेहतर बता रहे है।

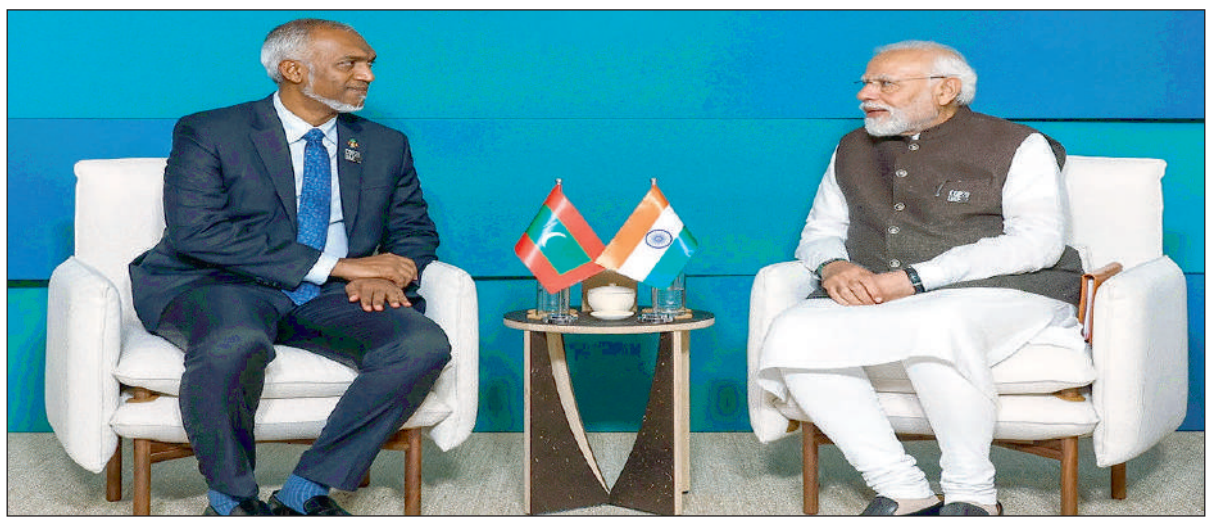

चीन की कटपुतली बने मालदीव को आखिर भारत की कीमत समझ में आ गयी। चीन एवं पाकिस्तान की कुचालों एवं षडयंत्रों से भारत के पडोसी देशों की हालात जर्जर होती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण बांग्लादेश है। लेकिन एक पडोसी देश के रूप में पिछले करीब एक साल की अवधि में मालदीव ने भी गहरे हिचकोले खाने एवं कई कड़वे अनुभवों से गुजरने के बाद अब पटरी पर आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पिछले सप्ताह हुई मालदीव यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का जैसा दोस्ताना रवैया देखने को मिला, जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ आगे बढ़ने की मंशा जाहिर की, यह उन्हें अपनी गलती का अहसास कराने का ही द्योतक कहा जा सकता है। देर आये दुरस्त आये वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भारत-मालदीव के रिश्तों को भावनात्मक राजनीति के तकाजों पर कूटनीति की ठोस हकीकतों की जीत के रूप में देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पूर्व कार्यकाल में पडोसी देशों की यात्रा करते हुए उनसे भारत के संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं विकासमूलक बनाने के प्रयास किये। इसी के तहत मोदी की तत्कालीन मालदीव दौरे का मुख्य उद्देश्य नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सुरक्षा, विकास की दृष्टि के भारत के संबंधों को और मजबूत करना था। दौरे के दौरान मोदी को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान 'निशान इजुद्दीन' से भी सम्मानित किया गया। दरअसल मालदीव की दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर में जो स्ट्रेटजिक (सामरिक) लोकेशन है, वह भारत के लिए बेहद अहम है। मालदीव में पिछले कुछ सालों में चीन ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया है, उसे हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर उल्लेखनीय सफलता भी मिली। लेकिन यह सब करने के पीछे चीन का मुख्य लक्ष्य मालदीव की भारत से दूरी बढ़ाना भी रहा, जिसमें उसे बड़ी सफलता मिली। इस प्रकरण की शुरुआत पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर मुइज्जू ने भारत विरोधी भावनाओं पर दांव लगाया था। वह बार-बार सार्वजनिक तौर पर यह संकल्प करते देखे गए कि सत्ता में पहुंचते ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से विदा कर देंगे। हालांकि सबको पता था कि भारतीय सैनिकों की वहां मौजूदगी सांकेतिक ही थी। भारत और मालदीव के बीच सदियों पुराने प्रेम एवं सौहार्द के रिश्ते एकाएक तल्ख होते दिखाई देने लगा। मालदीव की तरफ से लगातार तनाव बढ़ाने वाले बयान आते रहे, लेकिन भारत की तरफ से फिर भी संतुलित नीति अपनाई जाती रही है। इसी दौरान मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की, जिसका उद्देश्य कत्तई किसी भी देश के पर्यटन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने देश में पर्यटन की नई संभावनाओं को तलाशना है।

प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकाट मालदीव ट्रेंड होने लगा। इस हैशटैग के साथ लोगों के ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिसमें वे मालदीप और लक्षद्वीप की तुलना करते हुए लक्षद्वीप को बेहतर बता रहे है। मुइज्जू के भारत विरोध उनके अनेक मंत्रियों की तल्ख टिप्पणियों एवं रवैये के कारण वहां की अर्थ-व्यवस्था गिरने लगी, विशेषतः पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मालदीव की नई सरकार के रुख को देखते हुए भारत ने भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार कर ली। नतीजा यह हुआ कि भारत से छुट्टियां बिताने मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या कम होने लगी। इस साल के शुरुआती चार महीनों की अवधि में वहां भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 42 प्रतिशत घट गयी। ध्यान रहे, मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म का योगदान 30 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, भारत के सहयोग से चलने वाले इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स और हेल्थ, एजुकेशन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े कई प्रॉजेक्ट्स का भविष्य भी अधर में लटका दिखाई देने लगा। मुइज्जू सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती थी। किसी अन्य देश का सहयोग भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता था। ऐसे में मुइज्जू सरकार ने पिछले कुछ समय से अपने रुख में बदलाव का संकेत देना शुरू कर दिया था। भारत ने भी इन संकेतों का सम्मान किया। नतीजा यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की यात्रा की, जिसके कारण दो पड़ोसी देशों के पुराने रिश्ते फिर पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, लेकिन इन स्थितियों के कारण हुए भारी नुकसान का झेलते हुए मालदीव चीन के मनसूबों का भाप गया। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। यहां की नई सरकार चीन के करीब दिख रही है और चीन अपने मनसूंबो को पूरा करने के लिये गलत रास्तों पर ढकेल रहा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही 'इंडिया आउट' का नारा दिया था। भारत एवं मालदीव के बीच तल्खी अगर बढ़ती तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है।

चीन हमारे रिश्तों की तल्खी का फायदा उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है। जिसका भारत ने खयाल रखा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से संतुलित नीति पर बल दिया जाता रहा है, जबकि मालदीव की तरफ से तो लगातार काफी कुछ गलत कहा जाता रहा है। लेकिन मालदीव को भी यह समझ आ गया कि भारत से दूरी उसके लिये नुकसानदायी है। चीन की तुलना में भारत से मालदीव के हित ज्यादा गहराई से जुड़े हैं। फिर भी मुइज्जू भारत के साथ रिश्तों में आ रही संभावित दूरी की भरपाई चीन से करीबी रिश्तों के रूप में करना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स तब भी इस बात की ओर ध्यान खींच रहे थे कि भू-राजनीति की वास्तविकताओं के मद्देनजर यह संभव नहीं है कि मालदीव में जो भूमिका भारत निभा सकता है, वह चीन निभाने लगे। फिर भी चीन की शह पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश होती रही है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद मुइज्जू के बयानों में हलकी सी नरमी जरूर दिखी, लेकिन नीतियों की दिशा बदलने का प्रयास फिर भी जारी रहा। लेकिन इससे हो रहे नुकसान को लेकर मुइज्जू सरकार सतर्क हो गयी। पर्यटन ही मालदीव की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत से करीब दो लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमिशन के आंकड़ों को मानें तो साल 2022 में 2 लाख 41 हजार और 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में भारत-मालदीव के बीच बढ़ रही दूरी का असर मालदीव के टूरिज्म एवं आर्थिक व्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक था।

भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा रहा हैं लेकिन चीन पोषित भारत विरोध की ऐसी अकारण नफरत भारत क्यों बर्दाश्त करें? निश्चित ही मालदीव के रवैये का दोनों देशों के बीच की सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव पडा। भारतीय यदि मालदीव का बहिष्कार करने लगा तो वहां अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी, यह बात समझने में मालदीव को देर नहीं लगी। अपनी भूल को सुधारते हुए उसने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है जो दोनों देशों के हित में है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने में भारत सक्षम है, पडोसी देशों में भारत ही मजबूत स्थिति में है, आर्थिक एवं सामरिक दोनों ही दृष्टि से भारत अपने पडोसी देशों में सशक्त एवं ताकतवर है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV

Drive the Future

लखनऊ समेत चार शहरों में खोले जाएंगे चार्जिंग प्वाइंट स्टेशन, स्विच मोबिलिटी के साथ हुआ समझौता

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ, अयोध्या, बनारस और अलीगढ़ में ई-बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्टेशन खोले जाएंगे। प्रदेश भर के 17 शहरों के बीच चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों को इन स्टेशनों पर चार्ज किया जा सकेगा। परिवहन निगम ने चार्जिंग पॉइंट खोलने के लिए स्विच मोबिलिटी के साथ करार किया है।

कंपनी ने चार रूटों पर चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए सर्वे कराने के साथ ही जमीन की तलाश शुरू कर दी है। 180 से 250 किमी की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। रोडवेज बेड़े में शामिल होने वाली इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर 220 से 250 किमी तक चलेंगी। पांच हजार ई-बसों को अनुबंध पर चलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 325 करोड़ रुपये से 220 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए चार शहरों को चिह्नित किया गया है।

रोडवेज की ई-बसों के अलावा निजी ईवी वाहनों को भी चार्ज किया जा सकेगा।

-10 से अधिक प्लेटफॉर्म पर चार्जिंग के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे।

-चार्जिंग स्टेशन पर खान-पान और प्रदूषण जांच समेत कई सुविधाएं होंगी।

-स्लाइड चार्जिंग पर आधे घंटे में सभी तरह के वाहन चार्ज हो सकेंगे।

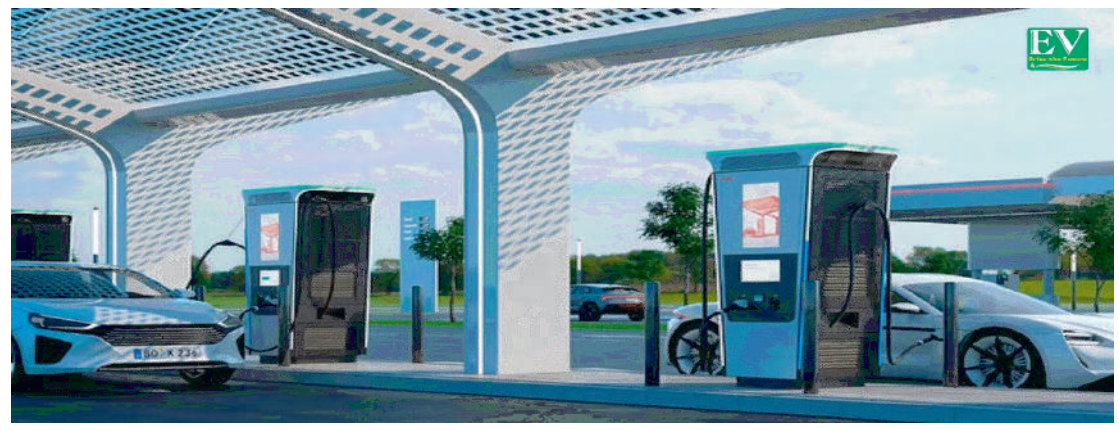

रांची के ई-रिक्शा चालक जाएं तो जाएं कहाँ, उनका तो कोई नहीं माई-बाप

परिवहन विशेष न्यूज

हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सपना था कि एक दिन वह हमारे देश में चल रहे असंख्य पैडल रिक्शा को ई-रिक्शा से बदल देंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई-रिक्शा हमारे देश की सड़कों पर आ चुके हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में कई घोषणाएं की हैं और समय-समय पर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होता है कि रांची के परिवहन विभाग में तैनात अधिकारी को इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के बारे में कुछ पता है या नहीं। इलेक्ट्रिक वाहनों को धारा 66 से छूट दी गई है, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर कभी भी कहीं भी जाने पर कोई रोक नहीं है। 18 अक्टूबर 2018 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर उद्देश्य बताया गया हैं। रांची के परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी है या नहीं, यह तो वे ही जानें।

रांची में इन दिनों ई-रिक्शा चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची नगर निगम को ई-रिक्शा चालक के घर के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ही रूट पास बनाना चाहिए था। निगम ने पास तो बनाया, लेकिन ई-रिक्शा चालक के घर से 25-30 किलोमीटर दूर बना दिया। जब ई-रिक्शा चालक अपने घर से रूट पास लेकर इलाके में जाता है, तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट देती है। इन चालानों में नगर निगम की ओर से तीन हजार, पांच हजार, 15 हजार और 25 हजार का जुर्माना लगाया जाता है।

जब ई-रिक्शा को शुरू में सड़कों पर उतारा गया था, तब वर्ष 2017 में लॉटरी के माध्यम से करीब 954 वाहनों को रूट पास मुहैया कराए गए थे। इसके बाद इसका कभी नवीनीकरण नहीं हुआ। उस समय इस पर किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब नगर निगम इस वाहन पर परमिट थोप रहा है।

विडंबना यह है कि वर्ष 2017 के बाद किसी भी तरह का रोड पास मुहैया नहीं कराया गया है। ई-रिक्शा चालकों का आरोप है कि अब प्रशासन की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है। पकड़े जाने पर इन ई-रिक्शा चालकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। यह जुर्माना 3 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक है।

ई-रिक्शा चालकों का कहना है, ₹हम मेहनत-मजदूरी करते हैं। दिनभर वाहन चलाते हैं, तभी हमारे घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अब हमारे घर के बच्चे भूखे सो रहे हैं। फिर जब घर की हालत देखकर हम वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। हम ब्याज पर पैसे लेकर चालान भरने को मजबूर हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है।"

रांची जिला ई-रिक्शा संघ के अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने बताया कि हमने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लॉटरी सिस्टम से दिए गए 954 ई-रिक्शा को आज सभी रूट पास होने के बावजूद जुर्माना भरना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की, ₹ई-रिक्शा को रूट पास से छूट दी जानी चाहिए। अगर किसी अन्य शहर में ऐसा नहीं है, तो हमारे रांची निगम में ऐसा क्यों है? ई-रिक्शा चालकों को जल्द ही सामान्य शुल्क पर रिक्शा स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना चाहिए, ताकि ई-रिक्शा का परिचालन सुचारू रूप से हो सके।"

इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवरी बेड़े का विस्तार करने के लिए अमेज़न इंडिया और जेंटारी ने की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

अमेजन इंडिया ने अपने ईवी परिनियोजन कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रिक परिवहन कंपनी जेंटारी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक अंतिम छोर तक डिलीवरी के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा तैयार करना है।

अमेजन इंडिया ने कहा कि सहयोग के तहत जेंटारी ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस अगले तीन वर्षों में कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तथा तैनाती करेगी। इसके अलावा ईवी बेड़े के निर्बाध संचालन तथा रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी सेवा भागीदारों (डीएसपी) को बेड़ा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से डिलीवरी सेवा प्रदाताओं (डीएसपी) को अमेजन डिलीवरी के लिए अधिक इलेक्ट्रिक तिपहिया तक पहुंच प्राप्त होगी।

अमेजन इंडिया ने कहा कि इस पार्टनरशिप के तहत जेंटारी ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस अगले 3 सालों में ई-कॉमर्स कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेगी और उनकी तैनाती भी करेगी। अमेजन इंडिया अभी देश भर के करीब 400 शहरों में बिजनेस कर रहा है।

इसके साथ ही जेंटारी ग्रीन मोबिलिटी ईवी फ्लीट के बेहतर संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स (डीएसपी) को फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करेगा। अमेजन इंडिया ने कहा कि इस पार्टनरशिप से डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स (डीएसपी) को अमेजन डिलीवरी के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर गाड़ियों तक पहुंच प्राप्त होगी। बताते चलें कि जेंटारी ग्रीन मोबिलिटी, मलेशिया की एनर्जी कंपनी पेट्रोनस पेट्रोनास की ही एक कंपनी है।

कटघोरा में खुलेगी देश की पहली लीथियम खदान

परिवहन विशेष न्यूज

छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का एक बड़ा भंडार खोजा गया है। इस खोज से चीन से लिथियम आयात पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आने और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण लागत में कमी आने की आशा है। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा लिथियम चीन से आयात करता है।

भारत का लक्ष्य अगले चार वर्षों में ईवी के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनना है। इस प्रकार लिथियम भंडारों को उपयोगी बैटरी सेल में विकसित करना कई चरणों वाली एक जटिल प्रक्रिया है। घरेलू लिथियम भंडार होना भारत की अर्थव्यवस्था और इसके बढ़ते ईवी उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार, 13 अगस्त को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6ठवीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खनिजों का दोहन और उनके उपयोग के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की भी चर्चा हुई। जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लीथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित रहने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में लीथियम एक अहम धातु है, जिससे राज्य और देश विकास की नई दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि लीथियम खदान के शुरु हो जाने से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और विकसित भारत 2047 के योगदान में छत्तीसगढ़ के लीथियम भंडार का बड़ा योगदान होगा।

भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी जारी किया गया है। इन 20 ब्लॉक्स

में से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लिथियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है।

लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जीएसआई द्वारा प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2 हजार पीपीएम लिथियम कन्टेन्ट पाया गया है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्युटिकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि में होती है। इस खनिज के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।

यह खोज देश के ईवी उद्योग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। देश का वार्षिक लिथियम-आयन बैटरी बाजार वित्त वर्ष 21 में 2.6 गीगावाट घंटा से बढ़कर वित्त वर्ष 30 तक 116 गीगावाट घंटा होने का अनुमान है, जिसमें ईवी इस बाजार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। बोलीविया में 21 मिलियन टन के साथ दुनिया भर में सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, उसके बाद अर्जेंटीना, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। मात्र 5.1 मिलियन टन भंडार होने के बावजूद, चीन वैश्विक बाजार पर हावी है।

मर्सिडीज की नई GLE 300d भारत में हुई लॉन्च; कीमत, फीचर्स और नई जानकारी पढ़िएं

परिवहन विशेष न्यूज

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने GLE 300d 4Matic AMG लाइन को 97.85 लाख रुपये की बेस एक्स-शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया है। इसमें पिछले वाले के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं। इसमें क्रोम ट्रिम स्ट्रिप के साथ AMG फ्रंट एप्रन और ब्लैक में डिफ्यूज़र-लुक इंसर्ट दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसमें और कौन से फीचर्स दिए गए हैं।

नई दिल्ली। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने GLE 300d 4Matic AMG को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। यह AMG लाइन वेरिएंट 300d एंट्री-लेवल डीजल वेरिएंट की जगह लेगा और इसे AMG-विशिष्ट कॉस्मेटिक अपडेट के साथ लाया गया है। आइए जानते हैं कि इसें कौन-कौन से नए फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे।

मर्सिडीज GLE 300d 4Matic AMG में क्या है नया?

इसमें ट्रेमोलाइट ग्रे में फिनिश किए गए 20-इंच AMG अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसमें आउटगोइंग मॉडल के मुकाबले आगे की तरफ बड़े डिस्क ब्रेक लगाया गया है। वहीं, क्रोम ट्रिम स्ट्रिप के साथ AMG फ्रंट एप्रन और ब्लैक में डिफ्यूज़र-लुक इंसर्ट और क्रोम में ट्रिम स्ट्रिप के साथ AMG रियर एप्रन दिया गया है।

इतना ही नहीं इसमें थ्री-पॉइंटेड स्टार पैटर्न के साथ डायमंड-ग्रिल, क्रोम इंसर्ट और ब्लैक सराउंड के साथ मैट डार्क ग्रे में पेंट किया गया है। वहीं, आगे की तरफ स्पोर्टियर एयर इनलेट और व्हीकल के कलर में पेंट की गई AMG साइड स्कर्ट दी गई है। यह GLE 300d के मुकाबले 1.2 लाख रुपये एक्सट्रा देना पड़ेगा।

कितना दमदार है मर्सिडीज GLE 300d 4Matic AMG का इंजन

नए 300d 4Matic AMG लाइन वैरिएंट में 2.0-लीटर चार-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 269hp और 550Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड इंटीग्रेटेड स्टार्टर-जनरेटर दिया गया है, जो पीक आउटपुट में अतिरिक्त 20hp और 200Nm टॉर्क पैदा करता है।

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता यूलर मोटर्स ने हरियाणा में 100 करोड़ रुपये की विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा का किया अनावरण

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन निर्माता यूलर मोटर्स ने मंगलवार, 13 अगस्त को हरियाणा के पलवल में अपनी विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा का अनावरण किया, जिसे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया गया है।

कंपनी ने कहा कि 5 लाख वर्ग फीट में फैले इस प्लांट में प्रति वर्ष 36,000 वाहनों का उत्पादन करने की क्षमता है और यह यूलर मोटर्स के राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में काम करेगा, जो इसके तिपहिया वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा।

यूलर मोटर्स ने कहा कि वह वित्त वर्ष 2025 तक 26 शहरों से 40 शहरों तक अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है।

यूलर मोटर्स में आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण प्रमुख गौरव कुमार ने कहा, ₹हमारी नई फैक्ट्री वाणिज्यिक 3-पहिया ईवी के विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह सुविधा हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और हमें अपने ग्राहकों और उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने वाले स्थानीय रूप से निर्मित वाहन देने में मदद करेगी।"

कंपनी ने कहा कि नए प्लांट में एक स्वचालित असेंबली लाइन है जो एक मालिकाना विनिर्माण निष्पादन प्रणाली (एमईएस) के माध्यम से जुड़ी हुई है, जो उत्पादन से लेकर डिलीवरी तक वाहन के जीवनचक्र को ट्रैक करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है।

कंपनी ने कहा कि प्लांट में एक समर्पित शिक्षण और विकास केंद्र कार्यबल को सही कौशल से लैस करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कंपनी ने कहा कि वर्तमान में इसमें 500 से अधिक लोग कार्यरत हैं और उनमें से 20 प्रतिशत महिलाएं हैं।

यूलर मोटर्स के संस्थापक और सीईओ सौरव कुमार ने कहा, ₹भारत में मोबिलिटी सेगमेंट में चल रहे परिवर्तन को केवल मजबूत स्थानीय उत्पादन और स्थानीय नवाचार के साथ ही पूरी तरह से साकार किया जा सकता है।"

आजादी के सही मायने की तलाश में

प्रो . वीना ठाकुर

आज के इस जाति, धर्म, भाषा और ऐसे ही अन्य मतभेदों में घिरे भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक ऐसे भारत का सपना देख रही हूं जहां सभी आपसी सहज प्रेम और सद्भाव से रहें, जहां महिलाएं सुरक्षित हों, जहां किसी से अन्याय न हो'

चलो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सफेद सूट पर तिरंगे में रंगा दुपट्टा या परना ओढ़ कर तिरंगा झंडा लहराते हैं, स्पीकर पर देशभक्ति के फिल्मी गीत बजाते हैं। देश भक्ति के गीतों पर हो हल्ला मचाते हैं। ओह ! एक जरूरी बात तो रह ही गई कि इन सबकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल कर अपना स्टेटस बनाते हैं। क्या वाकई बस, इतना भर ही है आजादी का मतलब और उसे मनाने का पर्व, या इससे आगे भी और बहुत कुछ है ? है तो क्या हम भूलते जा रहे हैं ? और फिर अगले दिन जब छोटे-छोटे तिरंगे यहां-वहां सडक़ों पर, कूड़े के ढेरों के आसपास गिरे पड़े दिखते हैं तो कई बार खुद से ही पूछना पड़ता है कि क्या हम उस आजादी को समझ पाए हैं जिसके लिए हमारे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, वो आजादी जिसके लिए आज भी हमारे वीर जवान सरहद पर तैनात हैं और हंसकर अपने सीने पर गोली खाकर भी वंदे मातरम्का जयघोष करते हैं। या कि आजादी का पर्व हमारे लिए मात्र मजाक बन कर रह गया है ? सवाल वाजिब होने के साथ-साथ लाजिमी भी है, जो इस पर सोचा जाए तो। लेकिन इस बारे सोचना भी जरूरी है। और आगे तक इस बारे टाला नहीं जा सकता।

क्या ये वाकई आजादी ही है जहां हम अपने अधिकारों की मांग करते हुए ट्रेन, बस, इमारतों को जलाते हुए अपने देश के बारे में न सोचकर केवल और केवल इतना भर सोचते हैं कि मुझे बस, मेरे हक की लड़ाई में जीत मिलनी चाहिए, बल्कि हक से ज्यादा ही मिलनी चाहिए और वो भी सबसे पहले। उस हक की लड़ाई में भले ही मेरा देश हार जाए तो हार जाए। मुझे मेरा हक मिले, पर मुझसे कोई मेरे फर्ज की बात न करे। जहां सारे हक तो मेरे हों, पर जब देश के प्रति फर्ज की या कुछ करने की बात आए, तो उसे व्यवस्था का हवाला देकर सरकार या किसी और की तरफ घुमाया जा सके। अजीब लगता है जब हम अपने अधिकारों की बात कर कत्र्तव्यों को भूल जाते हैं। क्या हमने केवल अधिकारों के लिए आजादी पाई है ? क्या केवल अपने अधिकारों की जंग लडऩा ही आजादी है ? क्या हुआ अगर मेरे देश का आम नागरिक बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया गया है और उसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। ये मेरे आजाद देश का वो तबका है जिसकी वोट से लोग सत्ता के मजे लेते हुए उसे ही भूल जाते हैं क्योंकि वो और उसका वोट है भी तो इतना सस्ता कि जिसे कुछ झूठे प्रलोभनों, कुछ पैसों, कुछ कागजी स्कीमों और कई बार तो कुछ बोतलों में भी मजे से खरीदा जा सकता है। जिस लोकतंत्र में लोक मुखिया होना चाहिए, उसी लोकतंत्र में सरकार बनते ही लोक हाशिए पर चला जाता है, आखिर क्यों ? कुछ अपवादों को छोड दें तो आज की राजनीति में जनता की सेवा की जगह जनता को लूटने ने ले ली है और अफसर अपनी बेलगाम अफसरशाही के अंधेरे कमरों में बंद हो रहे हैं। ऐसे में हम कहां हैं, देश कहां है और आजादी कहां ? और ये जो देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ऐसे में इनका अर्थ क्या रह जाता है ? एक ओर जहां आम आदमी को उत्पीडऩ और अन्याय से बचाने के लिए बनाए गए पुलिस और न्याय मंदिरों से ही हो रहे उत्पीडऩ की खबरें गाहे बगाहे मीडिया की सुर्खियां बनती रहती हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों में फैला भ्रष्टाचार एक दर्दनाक प्यारा हादसा होकर रह गया है।

ईमानदारी और कर्मठता के लिए मिलने वाले ईनाम पाने के लिए लगाई जाने वाली बेईमानी और भ्रष्टाचार की दौड़ भी पूरी तरह से हमारी व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। रिश्तों में घुली मतलब की बयार आपसी संबंधों को आज कमजोर बना रही है। ऐसा भी नहीं है कि हमने इतने सालो में कुछ भी अच्छा नहीं किया। हम कई क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष की यात्रा कर आए हैं। और ये सब हम देशवासियों की दिन-रात की मेहनत, देश के प्रति कुछ कर गुजरने के जज्बे और कुशल नेतृत्व का ही कमाल है। परंतु हम इस बात को भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि पल-पल गरीब-अमीर के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। हम लाख कोशिशों के बाद भी इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि जात-बिरादरी-धर्म-मतलबों, मजहबों में बंटे हुए समाज में रहना दिन-दिन दूभर होता जा रहा है। हम इसे भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि भाषा, जाति, नस्ल और ऐसे ही अन्य मुद्दों पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लड़ते रहें। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है कंधे से कंधा मिला कर चलने की। संकीर्ण जातीय, सांप्रदायिक, लैंगिक, भाषायी मतभेदों और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर आपस में मिलकर रहने की वैचारिक-राजनीतिक इच्छाशक्ति की। आपसी सद्भाव और प्यार की, देश के प्रति सच्चे लगाव की। सिर्फ कोरी जुबान से नहीं, अपितु मन की गहराइयों से इसकी माटी और भूमि को मां मानने और उसी मां के प्रति होने वाले लगाव, प्यार और चिंता के भाव की। देश को भी प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के सपनों और संकल्पों की और उन सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए हर तरह से समर्पित होने की।

77 साल बाद आज भी आजादी के मायने ढूंढने के मेरे प्रयास को कदापि मेरे निराशावादी होने का प्रमाण न मानकर मेरा आशावाद ही माना जाए कि आज के इस जाति, धर्म, भाषा और ऐसे ही अन्य मतभेदों में घिरे भारत में किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक ऐसे भारत का सपना देख रही हूं जहां सभी आपसी सहज प्रेम और सद्भाव से रहें, जहां महिलाएं सुरक्षित हों, जहां किसी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हुए जेब में रखे हुए नोट या सिफारिशी पत्र को टटोलने की जरूरत न पड़े। जहां बच्चे कमाने की मजबूरी में किसी ढाबे या किसी निर्माण स्थल पर न जाकर पढ़ाई के लिए स्कूलों में जाएं। जहां ज्ञान और मेहनत पर सिफारिश या अन्य कोई भी साधन भारी न पड़े। जहां न्याय न केवल सहज और सुलभ हो, बल्कि सबके लिए बराबर हो। मैं एक ऐसी सुबह के इंतजार में हूं जहां इन उम्मीदों को पूरा करते सपनों के भारत के लिए सामूहिक संकल्प लिए जाएं और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से सामूहिक प्रयास किए जाएं। बहरहाल, नई उम्मीदों के बीच समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस बार हमें उत्कृष्ट भारत के लिए संकल्प लेना होगा।

संपादक की कलम से

निराशाजनक ओलंपिक के बाद

पेरिस ओलंपिक, 2024 में भारत का सफर समाप्त हुआ। कुछ उपलब्धियां रहीं, कुछ 'पहली बार' के रिकॉर्ड बने, हॉकी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन कुल मिला कर सफर 'निराशाजनक' रहा। एक बार फिर भारत शीर्ष 70 देशों की सूची में नहीं है। भारत एक रजत पदक और 5 कांस्य पदकों के साथ 71वें स्थान पर रहा, जबकि टोक्यो ओलंपिक में हमारा स्थान 48वां था। 1996 के अटलांटा और 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में भी भारत मात्र 1-1 कांस्य पदक के साथ 71वें स्थान पर था। यह 1992 के बाद पहला मौका है, जब भारत पाकिस्तान (62वां स्थान) से पीछे रहा है। उस साल भारत खाली झोली लौटा था, जबकि पाकिस्तान एक कांस्य पदक हासिल करने में कामयाब रहा था। विश्व जनसंख्या में भारत की 18 फीसदी हिस्सेदारी है, लेकिन ओलंपिक पदक की उपलब्धि मात्र 0.5 फीसदी है। अर्थात इतनी-सी आबादी ही ओलंपिक पदक जीतने लायक है। यह आंकड़ा निराशाजनक ही नहीं, राष्ट्रीय अपमान भी है। ओलंपिक पदक का सीधा संबंध आबादी से नहीं है, क्योंकि एक लाख जनसंख्या वाले देश ने भी स्वर्ण पदक जीता है और 144 करोड़ की सर्वाधिक आबादी वाले भारत को एक-एक पदक के लिए तरसना पड़ता है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाडियों ने भाग लिया, लेकिन 16 खेलों में ही अपना हुनर दिखा पाए। उसमें भी मु ी भर सूरमाओं को छोड़ कर शेष फिसड्डी ही साबित हुए। चूंकि उन खिलाडियों ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लिहाजा हम उनकी प्रशंसा में तालियां बजाएं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इन खिलाडियों पर सरकारी कोष से 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह करदाता का ही पैसा था। खिलाडियों को प्रशिक्षण दिलाया गया, विदेशी कोच रखे गए, विदेश में खेलने के अवसर दिए गए और देश में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। इतना सब कुछ महज प्रतिनिधित्व के लिए नहीं किया गया। दिक्कत यह है कि हमारे अधिकतर खिलाड़ी 'चैम्पियन' की मानसिकता से ही नहीं खेले, लिहाजा 6 मुकाबलों में 8 खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे।

न जाने उन्हें चौथे स्थान से इतना लगाव क्यों हो गया है ? इस जमात में मीराबाई चानू (भारोत्तोलन), लक्ष्य सेन (बैडमिंटन), अर्जुन बाबुता (शूटिंग), मनु भाकर (शूटिंग), धीरज बोम्मदेवरा-अंकिता भक्त (तीरंदाजी), माहेश्वरी चौहान-अनंतजीत सिंह (स्कीट मिश्रित) आदि खिलाड़ी ऐसे ही हैं, जो जीत की दहलीज से वापस मुड़े हैं। लक्ष्य ने कांस्य पदक मुकाबले में पहला सैट जीत लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने खेल में आत्मसमर्पण ही कर दिया। मीराबाई मात्र एक किलोग्राम से पिछड़ गईं, जबकि वह टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता रही हैं। स्कीट जोड़ी भी चीन से मात्र एक अंक पिछड़ गई। मनु भाकर ने तो 10 मीटर पिस्टल में दो कांस्य पदक जीत कर इतिहास रचा है। वह 25 मीटर पिस्टल में, आखिरी पलों में, निशाना चूक गईं। यह कुछ हद तक क्षम्य है। बैडमिंटन में तो भारत को खाली हाथ लौटना पड़ा है। सात्विक-चिराग की विश्व विख्यात जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में ही घुटने टेक दिए। उनसे स्वर्ण पदक की अपेक्षाएं की जा रही थीं। भारत के खिलाडियों ने औसतन 29 करोड़ लोगों पर एक ओलंपिक पदक जीता है और वह भी स्वर्ण पदक नहीं, लिहाजा पेरिस ओलंपिक के दौरान एक बार भी भारत के राष्ट्रगान की धुन नहीं बजी। सिर्फ स्वर्ण पदक जीतने पर ही राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है। बहरहाल अब ओलंपिक खेलों का पटाक्षेप हो चुका है, लिहाजा भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय और अन्य हितधारकों को व्यापक विमर्श करना चाहिए कि लगातार प्रयासों के बावजूद भारत खेलों में पिछड़ा क्यों है ? यह सरोकार प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी और अब कोच प्रकाश पादुकोण ने भी उठाया है। खासकर लक्ष्य से सवाल किए हैं कि जीत के लिए उन्हें क्या चाहिए ? एक आखिरी उम्मीद विनेश फोगाट के संदर्भ में है कि खेल पंचाट उनके पक्ष में फैसला दे और भारतीय महिला पहलवान को रजत पदक का सम्मान मिल सके, लेकिन फिर भी भारतीय खिलाडियों का सकल प्रदर्शन 'निराशाजनक' ही आंका जाएगा।

राय

कैसा हिमाचल बना रहे

ऊना में एक दर्जन से अधिक मौत के मातम में बरसात के कहर ने हजारों तख्तियों पर चेतावनी लिख दी। बारिश बेशक तबाही के साथ बरसी, लेकिन इसके नीचे हमारा चरित्र बेगुनाह नहीं। हम ऐसा हिमाचल बना रहे हैं, जहां बरसात को हमने खूंखार बना दिया। ऊना की बाढ़ का ही विशेषण करें तो हर मौत के किरदार में हमारी प्रगति की मिसालें दोषी बन कर खड़ी हैं। जेजों की खड्ड में इनोवा की ताकत का जनाजा इसलिए निकला, क्योंकि बारिश की चेतावनी पद्धति विकसित नहीं हुई। जान जोखिम पर डालकर परिवहन के प्रति नागरिक लापरवाही का नतीजा है कि खड्ड ने इनोवा की सांसें रोक दीं। दूसरी ओर बाथड़ी खड्ड का रौद्र रूप क्या सिर्फ बरसात का उफान है या हमने इस तरह की त्रासदी को आसान बना दिया। जाहिर है रेत-बजरी से निकलती आर्थिकी ने अपने कुप्रबंधन का शिकार खड्डों में किया। यह विनाश की कोख है जिसमें सिर्फ मौत की चीखों का भयावह परिदृश्य आज अगर बाथड़ी के तटों को ललकार रहा है, तो कल कोई अन्य खड्ड, नाला या कूहल होगी। ऊना के उद्योग परिसर की उत्पादकता ने जिस तरह खड्ड के मुहाने को कंकाल बनाया, उससे निर्माण के खतरों ने बहकना सीख लिया। दरअसल हम बहते पानी पर बादल के फटने की तोहमत के पीछे नुकसान को छुपाना चाहते हैं, जबकि बरसात के लिए विकास का अवाधित तयशुदा प्रस्थान चाहिए।

आज बाथड़ी में औद्योगिक चहल-पहल पर बरसात का डाका पड़ा तो यह स्पष्ट हो गया कि वहां का निर्माण कातिल था। कौन सी ऐसी एजेंसी है जो यह बताने में सक्षम है कि कहां की जमीन किस कार्य या गतिविधि के लिए उपयुक्त है। तेज निर्माण को तेज धारा के जल से हमेशा खतरा रहेगा। हमारी जरूरतों का तात्कालिक महत्त्व जिस गति से विकास को आमंत्रित कर रहा है, वहां हमें निर्माण की आचार संहिता लागू करनी चाहिए। पंडोह का कैंची मोड़, रानीताल से गुजरता फोरलेन, खड़ामुख-होली मार्ग पर गिरती चट्टानें और हर निर्माण कार्य की डीपीआर कांप रही है। हमें बरसात से पहले और बारिश के बाद के मुआयनों से सीखना होगा। आश्चर्य यह कि बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों पर तवज्जो देते हुए प्रदेश को प्राकृतिक जल प्रणाली के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं, विकास तथा शहरीकरण की आवासीय व्यवस्था का अध्ययन करते हुए, जल निकास का प्रबंधन करना होगा।

हम राजनीतिक कारणों, भूमि की अनुपलब्धता या वनापत्तियों में हो रही देरी के कारण ऐसी भूमि पर कंक्रीट बिछाने की हिमाकत कर रहे हैं, जो बाद में खतरों का ठिकाना साबित हो रहे हैं। जलस्रोतों के आसपास अतिक्रमण और निर्माण की छूट ने पूरे हिमाचल को बरसात त्रासदी के हवाले कर दिया है। ऐसे में हिमाचल में व्यवस्थित निर्माण के लिए टीसीपी कानून को पूरे प्रदेश में अमल में लाना होगा, ताकि शहरी एवं ग्रामीण विकास को नियोजित ढंग से अमल में ला सकें। इसके अलावा निर्माण की आचार संहिता लागू करते हुए पहाड़, पर्यावरण और जल निकास की शर्तों का कठोरता से पालन किया जाए। सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने की वैधता को पूरा करने के लिए तंत्र सुधारना पड़ेगा।

आपदा की आवाजाही

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत तथा पुनर्वास का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इन नदियों के दोनों तरफ पूर्व में आपदा से प्रभावित हुए लोग श्रीनगर, उत्तरकाशी और केदारनाथ की तर्ज पर पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। यहां हालात बहुत चिंताजनक हैं। भारी बारिश के चलते डरे हुए माहौल में लोग रातें गुजार रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस तरह की न्यूनतम राशि की घोषणाएं अब तक हुई हैं, उसके कारण लोगों में रोष है। वहीं भिलंगना नदी की सहायक नैलचामी गाड के किनारे बसे हुए गांव में मिलने वाले एक गदेरे में आई भीषण बाढ़ ने तीन जानें ले लीं'

हिमालय और उसके राज्यों की मौजूदा आपदाएं आत्महंता विकास के विकराल नमूने बनते जा रहे हैं। इनसान अपना अंत किस नासमझी से जानबूझकर रचता है, इसे देखना-समझना हो तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के मौजूदा हालात का जायजा लिया जा सकता है। इस बार जितनी देर से बारिश शुरू हुई है, उतनी ही जल्दी जानलेवा आपदा आ गयी है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से चारधाम की सडक़ें ध्वस्त होने लगी थीं। आवागमन के पैदल रास्ते भी नदी में समा रहे थे। भगवान केदारनाथ इतना क्रोधित हैं कि वे भी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं कि लोग बरसात के समय बेवजह यात्रा करें। थोड़ा इंतजार करें, लेकिन मनुष्य ने तो प्रकृति पर पूरी तरह विजय करने की सोची है। वह हर घाटी से लेकर ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर प्रतिकूल मौसम में भी बिना सोचे-समझे जा रहा है। जहां-जहां मनुष्य के कदम पड़ रहे हैं, वहां धरती इतनी संवेदनशील बन गयी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ध्यान रहे कि चारधाम बरसात में सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा के नाम पर जितनी भी घोषणाएं करें, वे मौसम के सामने बौनी पड़ रही हैं। यहां हर साल आपदा का आकार बढ़ता ही जा रहा है। 2013 की केदारनाथ आपदा की तरह ही मंदाकिनी नदी में इस बार जल प्रलय जैसा रूप लोगों ने देखा है। स्थिति इतनी विकराल बन गई थी कि 2 अगस्त तक केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे लगभग 4000 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से लगभग 700 यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मंदाकिनी नदी में जलस्तर बढऩे से पैदल मार्ग पर रामवाड़ा में दो पुल और भीम बली में 25 मीटर रास्ता क्षतिग्रस्त होकर बह गया। यहां से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को मुश्किल से बचाया जा सका है।

पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। यदि पहले मौसम के अलर्ट पर ऋषिकेश में ही यात्रियों को जाने से रोक देते तो समय और खर्च दोनों को रोका जा सकता था। उत्तराखंड और हिमाचल में अब तक 22 लोगों की मौतें हो चुकी हैं जिनमें से 16 लोग उत्तराखंड में मलबे में दबकर मरे हैं और पांच लोग लापता हैं। हिमाचल में 6 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं। (इन आंकड़ों में रविवार को हुई दुर्घटना के आंकड़े शामिल नहीं हैं)। अब तक वहां पर 300 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 2023 की आपदा में भी हिमाचल में 12000 करोड़ का नुकसान हुआ था और लगभग 500 लोग मारे गए थे। इस बार अभी तक यहां दो पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए हैं

जिसके कारण दर्जनों लोग लापता हैं। आपदा की यह जानलेवा घटना कुल्लू, मंडी और रामपुर में अधिक हुई है। हिमाचल की 445 सडक़ें ठप्प पड़ी हैं जिनको खोलने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटकों ने आपदा की स्थिति को देखकर अपनी बुकिंग कैंसिल की है जिसके कारण पर्यटन कारोबार पिछले वर्ष की तरह प्रभावित हो गया है। कुल्लू-शिमला की सीमा पर समेज खड्ड में आई बाढ़ में लगभग तीन दर्जन मकान बह गए हैं। यहां 6 बच्चों समेत 36 लोग लापता हैं। सात घंटे में सामान्य से 305 मिलीमीटर ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगभग 7 पुल बह गए हैं। सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचने लगा है। यहां पर श्रीखंड महादेव मार्ग पर करीब 250 लोग फंसे हुए हैं।

रामपुर में आई बाढ़ से पांच घर, तीन गाडियां, पुल भी बह गए हैं। शिमला में भी कई जगह भूस्खलन और भू-धंसाव की घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं सबसे अधिक विनाश का कारण बन रही हैं। 2013 की केदारनाथ आपदा के समय भी 24 जल विद्युत परियोजनाओं ने मंदाकिनी और अलकनंदा घाटी का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसकी पुनरावृत्ति फिर से देखी जा रही है। जिला टिहरी गढ़वाल में बालगंगा और धर्मगंगा पर 26-27 जुलाई की भीषण बाढ़ ने जो विनाश लीला रची है, उसने केदारनाथ आपदा की याद ताजा कर दी है। यहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए प्रसिद्ध बूढ़ा केदारनाथ मंदिर भी है जिसके दोनों तरफ यह नदी बहती है। यहां 20 किलोमीटर के क्षेत्र में नदी तटों पर निर्माण कार्यों से एकत्रित मलबे के बहने से पैदा हुए भीषण जल प्रलय से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हुई है। लोगों के होटल, मकान, गौशालाएं नदी में समा गए हैं। यहां प्रसिद्ध समाजसेवी स्व. बिहारीलाल द्वारा बड़े बांध के विकल्प के रूप में 50 किलोवाट की एक छोटी पनबिजली परियोजना बनायी गई थी जो पूरी तरह मलबे में दब गई है। इससे आगे भी तीन मेगावाट की एक लघु जलविद्युत योजना ध्वस्त हो गई है। क्षेत्र के एक दर्जन पुल जर्जर हो चुके हैं। आवागमन के रास्ते टूट गए हैं। यहां पर तोली गांव में मां और बेटी की भूस्खलन में दबकर मौत हुई है। इसी के पास तिनगढ़ गांव के घरों में मलबा जमा हुआ है। प्रशासन ने एक इंटर कॉलेज में राहत शिविर लगाया है, जहां बाढ़ प्रभावितों को भोजन, पानी, रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत तथा पुनर्वास का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इन नदियों के दोनों तरफ पूर्व में आपदा से प्रभावित हुए लोग श्रीनगर, उत्तरकाशी और केदारनाथ की तर्ज पर पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं।

यहां हालात बहुत चिंताजनक हैं। भारी बारिश के चलते डरे हुए माहौल में लोग रातें गुजार रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस तरह की न्यूनतम राशि की घोषणाएं अब तक हुई हैं, उसके कारण लोगों में रोष है। वहीं भिलंगना नदी की सहायक नैलचामी गाड के किनारे बसे हुए जखन्याली नौताड गांव में मिलने वाले एक गदेरे में रात को आई भीषण बाढ़ ने पति-पत्नी और उनके बेटे की जान ले ली। गांव की खेती, पशु और घरों को बुरी तरह नुकसान हुआ है। यहां पर 10 साल पहले भी बाढ़ आई थी। तब छह लोग मारे गए थे। गांव के घर मलबे में दब गए थे। इसके बावजूद शेष गांव के हिस्से को बचाने के प्रयास नहीं होने से वही पुनरावृत्ति हुई है। उत्तरकाशी में भागीरथी और यमुना नदी के उद्गम पर भी भीषण बाढ़ के दृश्य सामने आए हैं, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं हो रहा है। हिमालय की भौगोलिक संरचना की अनदेखी करके अमल किए जा रहे विकास के तरीके विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हर साल जल प्रलय की बढ़ती घटनाओं में बह रही मिट्टी, पानी, पत्थर, पेड़, लोग आदि की चिंता बरसात पूरी होने पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद धरती-तोड़ विकास अनवरत चलता रहता है। फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है जो भोगवादी विलासितापूर्ण विकास का परिणाम है। हिमाचल में बारिश का तांडव अभी भी जारी है। रविवार को ऊना जिला में प्राकृतिक आपदा के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। अगर हमने प्रकृति का नासमझी से दोहन जारी रखा, तो इस तरह की आपदाओं को रोकना मुश्किल हो जाएगा।

तिनकों की दाढ़ी

पीए सिद्धार्थ

झुन्नू लाल अपने आंगन में ज़ोर-ज़ोर से गा रहे थे, 'चोर की दाढ़ी रहती, तिनकों की भरमार। कुछ तो जिह्वा से झरें, कुछ पैरों की मार।' अपने कौतुहल को रोक पाने में असमर्थ रहने पर मैं अपनी छत से उतर कर उनके घर जा पहुंचा। मुझे देखते ही वह चहकते हुए बोले, 'आओ महारथी ! तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं बोला कि मैंने तो चोर की दाढ़ी में तिनका ही सुना था। पर आप चोर की दाढ़ी में तिनकों की भरमार बता रहे हैं। मामला क्या है ?' वह हंसते हुए बोले, 'अब इस दोहे को भी बदलने का समय आ गया है। अब दाढ़ी में तिनकों की भरमार नहीं। लोगों की दाढ़ी ही तिनकों वाली हो गई है। उनका अंग-अंग तिनकों से भरा रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का खेल मंत्री संसद में बिना पूछे ही वजन के कारण महिला कुश्ती के फाइनल में अयोग्य ठहराई गई विनेश फोगाट के ऊपर सरकार द्वारा ख़र्च की गई राशि का ब्यौरा क्यों देता।' मैं बोला कि कमाल है अगर सरकार किसी खिलाड़ी के ऊपर ख़र्च करे तो क्या वह उसका एहसान भी न जतलाए। झुन्नू लाल तमकते हुए बोले, 'किसी मंत्री या प्रधान सेवक के बाप का पैसा है। टैक्स पेयर का पैसा है। हम जो अपनी तनख्वाह का करीब पचपन परसेंट टैक्स भर रहे हैं, उसी के बल पर यह सभी माननीय ऐश कर रहे हैं। कभी किसी मंत्री ने संसद में बताया कि सरकारी ख़र्चे पर जो चुनावी रैलियां आयोजित होती हैं, उस पर कितना ख़र्च आता है या खेल मंत्री ने संसद में बताया कि गुजरात से जो दो सूरमा ओलिम्पक्स से ख़ाली हाथ बजाते हुए वापिस लौटे, उन पर सरकार के कितना ख़र्च किया। तुम एहसान की बात करते हो। तुम्हारे प्रधान सेवक ने गुजरात के अपने दोनों खिलाडयों को ओलिम्पक्स में जाने से पहले ही कहा था कि तुम दोनों खेल भावना से खेलना।

सोना लाने की चिंता मत करना। सोने के लिए हम जो हैं। पिछले दस सालों से देश की समस्याओं पर चद्दर तान कर सो ही तो रहे हैं। बस तुम तो यह ख्याल रखना कि तुम्हारे जीतने से किसी दूसरे देश के खिलाड़ी की भावनाएं आहत न हों। जब अपने देश में कोई खेलने आए तो अतिथि देवो भवः का ध्यान रखना और कहीं बाहर खेलो तो किसी मेजबान का दिल मत दुखाना। हमारे लिए हार-जीत मायने नहीं रखती। खेल मायने रखता है। लेकिन खेल वही, जो हम खेलते हैं। जहां खेल भी हमारा होता है और शर्तें भी हमारी। फिर चाहे संसद हो, चुनाव आयोग हो, संवैधानिक संस्थाएं या फिर आम जनता। सरकारों को गिराना हो या उनकी खरीद-ओ-फरोख्त। खेल हमीं खेलते हैं। देखो हमारी पार्टी की सरकार में दूसरी पार्टियों के खरीदे हुए कितने नेता सांसद हैं। अगर वह न होते तो हम डेढ़ सौ तक भी नहीं पहुंचते। फिर हमारा चुनाव आयोग का खेल देखो। अगर हम चुनाव में नहीं खेलते तो आज पचास भी न होते। हमने खेल को खेल ही नहीं रखा। उसे कला का दरजा दिया है। गुजरात के दो खिलाडियों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। अगर हमारे खिलाड़ी हमारी तरह खेलें तो हर ओलिम्पक्स के कम से कम आधे गोल्ड हमारे हों। हां, बस चुनाव आयुक्तों और नौकरशाहों की तरह ओलिम्पक्स समिति में हमारे चुने हुए लोग होने चाहिए। बाक़ी काम तो हम उन्हें एक्सटेंशन देकर पूरा कर लेंगे।' मैंने कहा कि क्या बेहतर हो अगर प्रधान सेवक देश का पैसा लूट कर विदेश भागने वालों को भी गोल्ड मेडल दिलवाने की व्यवस्था करवा सकें तो। वह हंसते हुए बोले, 'अरे तुम नाहक चिंता करते हो। तुम्हें पता नहीं शायद। सरकार ऐसे लोगों को पहले ही गोल्ड मेडल दे देती है। सरकार से गोल्ड मेडल लेने के बाद ही तो ये सारे लोग भागने में कामयाब हो पाते हैं। नहीं तो उनके वीज़ा और भागने की व्यवस्था कौन करेगा। क्या ऐसे सूरमाओं के लिए हमारा सिस्टम इतना भी नहीं कर सकता।'

सोना चमका और चांदी के दाम रहे स्थिर, क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस?

पिछले सत्र में 99 .9 प्रतिशत शुद्धता वाला गोल्ड सोमवार को 72350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार मंगलवार को चांदी की कीमत 83500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। कॉमेक्स सोना सोमवार को 1.2 प्रतिशत बढ़कर 2504 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 27 .81 डॉलर प्रति औंस पर कम बोली गई।

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार से मजबूत संकेतों और घरेलू मांग में वृद्धि के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 500 रुपये बढ़कर 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं, मंगलवार को चांदी की कीमत 83,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।

सोना-चांदी का लेटेस्ट प्राइज

पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला गोल्ड सोमवार को 72,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार मंगलवार को चांदी की कीमत 83,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी पिछले बंद के मुकाबले 500 रुपये बढ़कर 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

व्यापारियों ने सोने की कीमतों में तेजी का श्रेय रिटेल सेल के साथ-साथ आभूषण विक्रेताओं की बढ़ती मांग को दिया। विदेशी बाजार में सोना 1.30 डॉलर प्रति औंस की तेजी के साथ 2,502.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

ग्लोबल मार्केट की स्थिति

कोटक सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च की एवीपी कायनात चैनवाला के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और 18 सितंबर की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण कॉमेक्स सोना सोमवार को 1.2 प्रतिशत बढ़कर 2,504 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 27.81 डॉलर प्रति औंस पर कम बोली गई।

एक्सपर्ट ने क्या कहा?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि इसके अलावा, इस बात की चिंता थी कि ईरान इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायल पर हमला कर सकता है, जिससे सोने के सुरक्षित-संपत्ति प्रीमियम में वृद्धि हुई है।

एंजेल वन में डीवीपी-रिसर्च, गैर-कृषि कमोडिटीज और करेंसीज प्रथमेश माल्या के अनुसार, व्यापारी आगामी अमेरिकी उत्पादक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जो फेड की ब्याज दर प्रक्षेपवक्र में आगे की जानकारी प्रदान कर सकता है।

आईआरसीटीसी ने जारी किया तिमाही नतीजा
33 फीसदी बढ़ा मुनाफा, शेयरों पर रखें नजर

परिवहन विशेष न्यूज

IRCTC का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 73340 करोड़ रुपये है। 13 अगस्त को IRCTC के शेयर बीएसई पर 0 .65 फीसदी की गिरावट के साथ 918 .30 रुपये पर बंद हुए। पिछले तीन महीनों में शेयर में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले एक साल में निवेशकों को 40 फीसदी से अधिक मुनाफा हुआ है। अक्टूबर 2018 में लिस्टिंग के बाद से IRCTC ने करीब 500 फीसदी का रिटर्न दिया है।

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 33.3 फीसदी अधिक है। IRCTC के मुनाफे में बढ़ोतरी की बड़ी वजह टिकट बिक्री रही, जिसमें बड़ा उछाल आया है।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ट्रेन में खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाली ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसका रेवेन्यू 11.8 फीसदी बढ़कर 1,120.15 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, कंपनी ने मुनाफे के लिए विश्लेषकों की उम्मीदों को पार कर लिया, लेकिन टॉपलाइन की उम्मीदों से थोड़ा चूक गई।

घरेलू ब्रोकिंग फर्म प्रभुदास लीलाधर का अनुमान था कि कंपनी 306.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज करेगी, जबकि शुद्ध बिक्री बढ़कर 1,130.8 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी। 31 मार्च, 2024 को खत्म तिमाही में कंपनी ने 1154.8 करोड़ रुपये की कंसालिडेटेड सेल और 284.18 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

IRCTC का मार्केट कैप

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार, IRCTC का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 73,340 करोड़ रुपये है। 13 अगस्त को IRCTC के शेयर बीएसई पर 0.65 फीसदी की गिरावट के साथ 918.30 रुपये पर बंद हुए। पिछले तीन महीनों में शेयर में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक साल की बात करें, तो निवेशकों को 40 फीसदी से अधिक मुनाफा हुआ है। अक्टूबर 2018 में लिस्टिंग के बाद से IRCTC ने करीब 500 फीसदी का रिटर्न दिया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो IRCTC में सरकार के पास हिस्सेदारी 62.4 फीसदी शेयर है। वहीं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत शेयर हैं। जनता की होल्डिंग 20 फीसदी है।

क्या करती है IRCTC

IRCTC इकलौती कंपनी है, जिसे सरकार ने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग और रेल में खानपान सेवा उपलब्ध कराने का जिम्मा दे रखा है। यह रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में पैकेज्ड पानी भी उपलब्ध कराती है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। इसमें लग्जरी ट्रेन टूर, होटल बुकिंग और हॉलिडे पैकेज जैसी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की एक विस्तृत चेन शामिल है।

यस बैंक से SBI को होगा 100 अरब का मुनाफा! जापान और दुबई के बैंकों को हिस्सेदारी बेचने की तैयारी

यस बैंक साल 2020 की शुरुआत में डूबने की कगार पर पहुंच गया था। इसे बचाने के लिए आरबीआई ने स्थानीय बैंकों का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने निवेश करके यस बैंक बचाया। SBI के पास फिलहाल यस बैंक में सबसे अधिक 24 फीसदी हिस्सेदारी है। अब SBI अपनी स्टेक बेचकर यस बैंक से बाहर निकलने की तैयारी में है। उसे आरबीआई से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है।

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगले साल की शुरुआत तक यस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहता है। एसबीआई का यस बैंक में करीब 24 फीसदी स्टेक है और इस सौदे की कीमत तकरीबन 184.2 अरब रुपये हो सकती है। डॉलर में कहें, तो 2.2 अरब। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी है।

कौन खरीदेगा SBI की हिस्सेदारी

जापानी बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और दुबई का एमिरेट्स NBD फिलहाल यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में सबसे आगे हैं। सुमितोमो मित्सुई जापान के दूसरे बड़े बैंक सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की सहयोगी कंपनी है। दोनों ही बिडर्स ने यस बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, ताकि उनका बिजनेस पर पूरी तरह कंट्रोल रहे।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिजर्व बैंक (RBI) ने मौखिक तौर पर एसबीआई के हिस्सेदारी बेचने वाले प्रस्ताव को रजामंदी दे दी है और अब आगे की प्रक्रिया पर काम हो रहा है।

SBI ने क्यों खरीदी थी हिस्सेदारी

साल 2020 की शुरुआत में यस बैंक बड़े वित्तीय संकट में फंस गया। उसने अधिकांश कर्ज उन कंपनियों को दे रखा था, जो घाटे में चल रही थीं। ऐसे में उसे समय पर लोन के पैसे वापस नहीं मिले और वह डूबने की कगार पर पहुंच गया। उसके शेयरों की कीमत 2018 में 400 के करीब थी, जो मार्च 2020 तक 15 रुपये के आसपास आ गई।

अर्थव्यवस्था भरेगी उड़ान: 22 फीसदी बढ़ा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन में भी उछाल

परिवहन विशेष न्यूज

मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स से 22 .07 लाख करोड़ रुपये कलेक्ट करने का लक्ष्य है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में अच्छी ग्रोथ दिखी। साथ ही जीएसटी कलेक्शन भी जुलाई में 1.82 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। उच्च कर संग्रह देश के राजकोषीय घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इससे रोजगार पैदा होने

नई दिल्ली। भारत के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जोरदार इजाफा हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक (1 अप्रैल से 11 अगस्त तक) नेट डायरेक्ट कलेक्शन 22.5 फीसदी बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपये हो गया। इससे उम्मीद है कि भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहेगा और आर्थिक तरक्की की रफ्तार तेज होगी।

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 4.47 लाख करोड़ रुपये का पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) और 2.22 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन शामिल है। सरकार के हालिया डेटा के मुताबिक, सिक्योरिटीज टैक्स (एसटीटी) से 21,599 करोड़ रुपये मिले। वहीं, अन्य करों से 1,617 करोड़ रुपये मिले, जिसमें इक्वालाइजेशन और गिफ्ट टैक्स शामिल हैं।

कितना जारी हुआ रिफंड

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए। यह सालाना आधार 33.49 प्रतिशत अधिक है। ग्रॉस बेसिस पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24 प्रतिशत बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस कलेक्शन में 4.82 लाख करोड़ रुपये का PIT और 3.08 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है।

मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स से 22.07 लाख करोड़ रुपये कलेक्ट करने का लक्ष्य है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में अच्छी ग्रोथ दिखी। साथ ही, जीएसटी कलेक्शन भी जुलाई में 1.82 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। इससे जाहिर होता है कि सरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उच्च कर संग्रह देश के राजकोषीय घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में मदद करते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.9 प्रतिशत पर तय किया है। वित्त मंत्री ने कहा, ₹वित्त वर्ष 2023-24 में यह क्रमशः 14.01 लाख करोड़ रुपये और 11.63 लाख करोड़ रुपये होगा।₹ सरकार द्वारा उधारी में कमी से बैंकिंग प्रणाली में कंपनियों के पास निवेश के लिए उधार लेने के लिए अधिक पैसा बचेगा, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बेचने वाली है सरकार? क्या बढ़ेंगी टेलीकॉम कंपनी की मुश्किलें

सरकार की फिलहाल वोडाफोन आइडिया में 23 .18 फीसदी हिस्सेदारी है। पिछले हफ्ते मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी सॉवरेन वेल्थ फंड्स को बेचने के बारे में विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रक्रिया अभी बस शुरुआती दौर में है। इस मामले में अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी कतर इनवेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के टेमासेक से संपर्क किया गया है।

नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) वित्तीय तौर पर भारी मुश्किलों से जूझ रही है। यह टेलीकॉम कंपनी पिछले साल फरवरी में डूबने के कगार पर थी। लेकिन, सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी। इस कन्वर्जन से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी में 33 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई।

अब वोडाफोन आइडिया की अर्निंग कॉल में सीईओ अक्षय मूंदड़ा से सवाल किया गया कि क्या सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को सॉवरेन फंड्स को बेचने की तैयारी में है। इस पर मूंदड़ा ने कहा, 'हमारी हिस्सेदारी बेचने के मामले में सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारा मानना है कि सरकार पब्लिक शेयरहोल्डर के तौर पर अपने निवेश के मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यह हमारे दखल वाला विषय नहीं है।'

सरकार के पास 23.18 फीसदी हिस्सेदारी

सरकार की फिलहाल वोडाफोन आइडिया में 23.18 फीसदी हिस्सेदारी है। पिछले हफ्ते मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी सॉवरेन वेल्थ फंड्स को बेचने के बारे में विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रक्रिया अभी बस शुरुआती दौर में है। इस मामले में अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इनवेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के टेमासेक से संपर्क किया गया है।

वोडाफोन आइडिया के CEO मूंदड़ा ने कहा, 'मैं इस मामले में बस इतना कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी शेयरहोल्डिंग जारी रखे, इसे डायवर्ट करे या फिर कुछ और करे, यह उसका नीतिगत मामला है। बतौर कंपनी हमें इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है।'

वोडा आइडिया पर 2 लाख करोड़ बकाया

30 जून 2024 तक के डेटा मुताबिक, वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 2.09 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इसमें डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट के मद में 1.39 लाख करोड़ रुपये बाकी हैं। वहीं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) देनदारी 70,320 करोड़ रुपये है। AGR संबंधी बकाया को लेकर कोर्ट के एक पुराने आदेश के खिलाफ कंपनी ने की क्यूरेटिव याचिका दायर की है। इसके बारे में मूंदड़ा ने कहा कि कंपनी को मामले की खुली सुनवाई का इंतजार है।

वोडाफोन आइडिया के शेयर 3.37 फीसदी की गिरावट के साथ 15.47 रुपये पर आ गया। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों 5 फीसदी का उछाल आया है। वहीं, एक साल में इसने निवेशकों को 90 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है।

हेल्थ इंश्योरेंस से हट सकता है जीएसटी, काउंसिल की 54वीं बैठक में होगी चर्चा

जीवन और स्वास्थ्य बीमा से मिलने वाले जीएसटी का 72 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के खातों में जाता है। पिछले तीन वर्ष में जीवन-स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से 24529 करोड़ रुपए मिले। वहीं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से 2023-24 में 8262.94 करोड़ रुपये मिले। जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से 2023-24 में 1484 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक नौ सितंबर को होने जा रही है। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी दरों को या तो कम किया जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह खत्म किए जाने पर चर्चा हो सकती है।

संभव है कि केंद्र की ओर से ही इसका विचार रखा जाए। हालांकि देखना यह होगा कि इसके समर्थन में कितने राज्य आते हैं। बता दें कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा से मिलने वाले जीएसटी का 72 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के खातों में जाता है जबकि 28 प्रतिशत केंद्र के पास रहता है। बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव एवं उसे तर्कसंगत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी।

9 सितंबर को होगी GST काउंसिल की बैठक

दरअसल, हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को लेकर कुछ दिनों पहले तब राजनीतिक गर्मी बढ़ गई थी जब कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इसके बहाने केंद्र पर लोगों के स्वास्थ्य से भी पैसा कमाने की बात कही थी।

विपक्ष को इसलिए और भी अवसर मिल गया गया था, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस संबंध में वित्त मंत्री को संसद सत्र के दौरान पत्र लिखा था। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को ही कठघरे में खड़ा किया था। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से कहा था कि इस मुद्दे को वे अपने राज्य के वित्त मंत्रियों के समक्ष क्यों नहीं उठाते हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा था कि राज्यों के वित्त मंत्री ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से जो राजस्व मिलता है, उनमें आधी हिस्सेदारी सीधे तौर पर राज्यों को मिलती है और केंद्र को मिलने वाली 50 प्रतिशत राशि में से भी 41 प्रतिशत राशि सभी राज्यों में वितरित हो जाती है।

सरकारी बीमा योजनाओं पर जीएसटी नहीं

काउंसिल की बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म या इसमें कमी की जाती है तो इससे इंश्योरेंस खरीदार को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की तरफ चलाई जा रही इंश्योरेंस स्कीम पर जीएसटी नहीं लगता है।

स्लैब में बदलाव पर विचार काफी समय से लंबित जून में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया था कि आगामी बैठक में जीएसटी की विभिन्न दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फिटमेंट कमेटी बना दी गई है और कमेटी की रिपोर्ट या पहले की फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी की दरों में बदलाव पर फैसला होगा। बैठक में जीएसटी दरों के स्लैब में भी विचार किया जा सकता है।

'सपा का राजनीतिक डीएनए ही अपराध और अपराधी का साथ देना', कन्नौज रेप केस पर भाजपा का जोरदार हमला

परिवहन विशेष न्यूज

अयोध्या के बाद कन्नौज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा का राजनीतिक डीएनए ही अपराध और अपराधी का साथ देना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी के होंठ इन घटनाओं पर क्यों सिल जाते हैं।

नई दिल्ली। अयोध्या के बाद कन्नौज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में समाजवादी पार्टी के रुख पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सपा का राजनीतिक डीएनए ही अपराध और अपराधी का साथ देना है। इसी तरह से कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की सीबीआइ जांच के लिए समय मांगने को लेकर भी भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया

साथ ही उन्होंने अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटनाओं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' कहने वाली प्रियंका गांधी के होंठ इन घटनाओं पर क्यों सिल जाते हैं।

समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बुलंद हुए अपराध

सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने के साथ ही गंभीर अपराधों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया। कहा कि अपराध एक तरफ है, लेकिन अपराध के प्रति असंवेदनशीलता उससे भी बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बुलंद होते थे। उनके अनुसार, जब से यूपी के दो लड़कों (राहुल गांधी और अखिलेश यादव) की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत बढ़ती जा रही है।

राजनीति की गई, सपा नेता तरह-तरह के बयान दे रहे

भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, अपराध और अपराधी के जात-पात, पंथ और मजहब को राजनीति के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे अपराधी के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन अयोध्या में एक सपा नेता मोइद खान द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी वीभत्स घटना पर भी निर्लज्जता के साथ राजनीति की गई। वहीं, कन्नौज में दुष्कर्म के आरोपित से कन्नी काटने के लिए सपा नेता तरह-तरह के बयान दे रहे हैं।

इन घटनाओं पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की सियासी दुकान में मोहब्बत सिर्फ अपराधियों, आतंक के आरोपितों, भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों और दुष्कर्मियों के लिए है।

वायनाड में कैसे आई आपदा? पांच सदस्यीय टीम करेगी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जांच

केरल में पिछले दिनों हुए भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। भूस्खलन की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी जान मथाई करेंगे। टीम के सदस्य वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों दौरा कर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली आपदा के कारणों का आकलन करेंगे। बता दें कि लापता लोगों की तलाश 15वें दिन भी जारी रही।

वायनाड। केरल में पिछले दिनों हुए भूस्खलन की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी जान मथाई करेंगे। टीम के सदस्य वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों दौरा कर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली आपदा के कारणों का आकलन करेंगे। वहीं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के मद्देनजर राज्य सरकार को पुनर्वास योजना बनानी होगी।

15वें दिन भी जारी रही तलाश

लापता लोगों की तलाश 15वें दिन भी जारी रही। टीम आपदा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और आसपास के स्थलों में संभावित खतरों का आकलन करेगी। इसमें आपदा कैसे आई और भूस्खलन क्यों हुआ, इसका पता लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के बाद विशेषज्ञ दल अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और क्षेत्र के लिए उपयुक्त भूमि उपयोग की सिफारिश भी करेगा।

'पुनर्वास में संसाधनों की कमी सामने नहीं आएगी'

इस विशेषज्ञ दल के अन्य सदस्य जल संबंधित आपदा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र (सीडब्ल्यूआरएम) के प्रधान विज्ञानी और प्रमुख डा टीके , सुरथकल एनआइटी के सहायक प्रोफेसर डा श्रीवालसा कोलाथयार, जिला मृदा संरक्षण अधिकारी तारा मनोहरन और केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के खतरा एवं जोखिम विश्लेषक पी प्रदीप हैं।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि वायनाड जिले में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में संसाधनों की कमी सामने नहीं आएगी। अब इसके लिए विस्तृत योजना तैयार करना राज्य सरकार का काम है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों के लिए देश भर से मदद आ रही है।

जन जागरण अभियान के दौरान बिजेड़ी जमीन पर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का प्रयास करेगी

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेश्वर: 16 अगस्त से बिजेड़ी हर पंचायत में जन जागरण अभियान चलाएगी । पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भक्तों को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है । भाजपा के वादों पर पानी फिर गया। वरिष्ठ नागरिकों एवं राज्यवासियों के साथ धोखा किया गया है, जिससे जनता में असंतोष व्याप्त है ।बिजेड़ी को 24 साल बाद अपदस्थ कर दिया गया है ।जमीन पर भी स्थिति तब तक मजबूत रही जब तक वे सत्ता में रहे । सत्ता खोने के बाद जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है । नतीजा यह है कि पार्टी का कब्जा धीरे-धीरे ढह रहा है और डर बढ़ता जा रहा है । विभिन्न जिलों में कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के नेता भी पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं । इसलिए बीजेडी जनजागरण अभियान के माध्यम से हर पंचायत में अपना पुराना कब्जा बरकरार रखने का प्रयास करेगी । अभियान से पहले ही बीजू युवा और छात्र जनता पार्टी के अध्यक्ष जिले-जिले जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं । उन्होंने पूर्ववर्ती बीजेडी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को कहा ।पिछले पंचायत और नगर निगम चुनाव में बिजेड़ी को बड़ी सफलता मिली थी । पार्टी अब संगठन को व्यवस्थित करने पर ध्यान दे रही है क्योंकि दो साल बाद चुनाव होने हैं। जन जागरण अभियान के दौरान बिजेड़ी जमीन पर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का प्रयास करेगी । यदि पंचायत के ग्राम प्रतिनिधि ने अभियान शुरू कर दिया है तो जमीनी स्थिति मजबूत नहीं होने पर बिजेड़ी को अपनी स्थिति गंवानी पड़ सकती है । इसलिए पार्टी प्रदेश की पंचायतों से भाजपा सरकार के खिलाफ जंग शुरू करने जा रही है।

जेपी नड्डा से मिलने के बाद फोर्डा ने वापस ली हड़ताल, कहा- मान ली गई सारी मांगें

परिवहन विशेष न्यूज

कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर देशभर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं।

नईदिल्ली। कोलकाता में डाक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में फेडरेशन आफ रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) इंडिया के आह्वान पर जारी हड़ताल वापस ले ली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फोर्डा के प्रतिनिधिमंडल ने देर शाम यह घोषणा की।

मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि मरीजों की परेशनियों को देखते हुए बुधवार सुबह से डाक्टर काम पर लौट आएंगे। इसके पहले मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में डाक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

एम्स, सफदरजंग में हड़ताल रहेगी

फोर्डा के अध्यक्ष डा. अविरल माथुर ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। सेंटर हेल्थकेयर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार 15 दिन में एक कमेटी गठित करेगी। जिसमें फोर्डा के पदाधिकारी शामिल होंगे। सुबह दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डाक्टर ड्यूटी पर लौट सकते हैं। लेकिन एम्स और सफदरजंग अस्पताल के आरडीए ने हड़ताल वापस नहीं ली है। एम्स, सफदरजंग में हड़ताल रहेगी। उधर, एम्स आरडीए के अध्यक्ष डा इंद्र शेखर का कहना है कि सेंट्रल हेल्थकेयर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए पहले भी आश्वासन मिला था लेकिन बात आश्वासन से आगे नहीं बढ़ी। सरकार गारंटी दे और सेंट्रल हेल्थकेयर प्रोटेक्शन बिल संसद में लाकर पास कराकर कानून बनाने की समय सीमा निर्धारित करें तब हड़ताल वापस ली जाएगी।

भारतीय सामाजिक बैभब है समाजबाद : प्रभात त्रिपाठी

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वर : समाजवादी नेता श्री प्रभात त्रिपाठी; वरिष्ठ बीजद नेता और पूर्व विधायक बांकी ने हमारे संवाददाता से बात की... जहां मधु लिमये नहीं हैं, मधु दंडवते, रवि राय, यहां नहीं थे, इसलिए वह क्षण प्रभात त्रिपाठी पूर्व मुख्य सचेतक बीजद से बोलता है, उनके मुंह से वह कहते हैं कि जहां समाजवाद है वह पीछे हटना या नीचे जाना है, जहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जहां पूंजीवाद अब बढ़ रहा है, जहां हमारी बुद्धिमत्ता अब है, इसलिए पूर्व मुख्य सचेतक प्रवत त्रिपाठी ने स्नातकोत्तर इतिहास के बाद भद्रक स्वायत्त कॉलेज से अपना करियर शुरू किया, उन्होंने एमएस लॉ कॉलेज में एलएलबी पूरा किया, इसलिए जय प्रकाश आंदोलन से प्रवत त्रिपाठी आधुनिक समाजवाद आंदोलन, आम संपत्ति के इक्विटी वितरण को शुरू करने के लिए बहुत सक्रिय थे, जबकि 1971 में, वे कॉर्पोरेटीब थे, फिर उन्होंने अपना करियर शुरू किया, बीजद की कुछ जांच सीबीआई के आरोप पर सतही तौर पर सत्यापन के लिए की जा रही है, लेकिन इस बीच पर्वत त्रिपाठी यह साबित करते हैं कि उनके पास जो सोसाइटी का पैसा है, उसमें बांकी महोत्सव का प्रावधान है। लेकिन आखिरकार वह चाहते हैं कि समाजवाद में कल्याणकारी देश हो, जहां उनके रहने पर लोगों को भी उसी के अनुसार रहना चाहिए। इसलिए प्रभात त्रिपाठी उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और समाज के अग्रदूत हैं। वह समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस नहीं हैं। इसलिए कारगिल युद्ध के मद्देनजर ताबूत कहां बेचा जाए... लेकिन प्रभात त्रिपाठी अब समाजवादी नेता के रूप में कुछ विचारों, समाजवादी शक्तियों को जीते हैं, लेकिन अब भारत में अंधकारमय समय में समाजवादी विचार वह हर राजनीतिक दल की विचारधारा में एक नई गति ला सकते हैं, जो वैश्वीकरण को प्राथमिकता देते हुए व्यापार नीति पर उदारीकरण कर सकते हैं ।

भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाल मनाया आजादी का जश्न, शहर में वंदे मातरम की गूंज

परिवहन विशेष न्यूज

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला भाजपा संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस एवं विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत आज शहर में तिरंगा यात्रा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में निकाली गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद दामोदर अग्रवाल ने रैली को तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विट्ठलशंकर अवस्थी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि सांगानेरी गेट स्थित शहीद चौक से तिरंगा यात्रा में सैंकड़ों की संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि, जिला एवं मोर्चों के पदाधिकारी, शास्त्री, सुभाष, प्रताप, गणेश मंडल के पदाधिकारी, युवा, महिलाएं दोपहिया वाहनों पर रैली के रूप में रवाना हुए। तिरंगा यात्रा धानमंडी, बड़ा मंदिर, गुलमंडी, भीमगंज, गोलप्याऊ चौराहा होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रैली में वाहनों पर लगे तिरंगों और वन्देमातरम, भारत माता की जय जैसे उद्घोषों से समूचा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। रैली का पूरे मार्ग में जगह जगह आमजन एवं व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया।

तिरंगा यात्रा रैली में सभापति राकेश पाठक, जिला महामंत्री राजकुमार आंचलिया, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी, श्रीमती मंजू चेचाणी, जिला मंत्री गोपाल तेली, सुरेंद्र सिंह मोटरास, अमित सारस्वत, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, अध्यक्षीय प्रवास प्रमुख मनोज बुलानी, सोशल मीडिया संयोजक अजीत केसावत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष भगवतसिंह खैराबाद, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष पूरण डीडवानिया, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष इमरान कायमखानी, अनिल जैन, मनीष पालीवाल, पीयूष डाड, अनिल सिंह जादौन, अर्पित समदानी, लक्ष्यराज सिंह, सूरज सिंह, दीपक पाराशर, नंदलाल गुर्जर, रोशन मेघवंशी, लवकुमार जोशी, ललित व्यास, मुकेश शर्मा देबू, मुकेश चेचाणी, सज्जन सुथार, प्रेम विश्नोई, रेखा परिहार, इंदु बंसल, सुमित्रा पोरवाल, नेहा नागर, आरती कोगटा, रेखा शर्मा, देवेंद्र सिंह, रवि पूरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सुनने में असमर्थ लोगों के लिए दूरदर्शन पर खबरों के इंतजाम को लेकर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनने में असमर्थ लोगों के लिए दूरदर्शन पर रोजाना ताजा खबरों का इंतजाम करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि दूरदर्शन दिन में एक बार सबटाइटल के साथ न्यूज क्यों नहीं प्रसारित कर सकता। दूरदर्शन ऐसा कल से ही शुरू क्यों नहीं कर सकता

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने में असमर्थ लोगों के लिए दूरदर्शन पर रोजाना ताजा खबरों का इंतजाम करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि दूरदर्शन दिन में एक बार सबटाइटल के साथ न्यूज क्यों नहीं प्रसारित कर सकता। दूरदर्शन ऐसा कल से ही शुरू क्यों नहीं कर सकता?

मामले में 28 अगस्त को फिर सुनवाई होगी

कोर्ट ने केंद्र की पैरोकारी कर रही एडीशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से इस संबंध में प्रसार भारती से निर्देश लेने को कहा है। इतना ही नहीं, शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सकारात्मक जवाब लेकर आएं, नहीं तो कोर्ट आदेश देगा। मामले में 28 अगस्त को फिर सुनवाई होगी।

ये निर्देश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने गैर सरकारी संगठन संकेत फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। 2019 से लंबित याचिका में सुनने में असमर्थ लोगों के मनोरंजन के लिए निर्देश मांगा गया है। कहा गया है कि फिल्मों और न्यूज को सबटाइटल के साथ जारी किया जाए।

सुनने में असमर्थ लोगों के लिए कही ये बात

संस्था के वकील ने कोर्ट से कहा कि सबटाइटल ओपेन कैप्शन के साथ होने चाहिए न कि क्लोज कैप्शन के साथ। उनका कहना था कि क्लोज कैप्शन एआइ से तैयार होता है, इसलिए पूरी तरह सही नहीं होता। कैप्शन साथ जारी होने से जो लोग सुनने में असमर्थ हैं, वे भी मनोरंजन कर सकेंगे। फिल्म के बारे में उनका यह भी सुझाव था कि अगर सभी शो में संभव न हो तो कम से कम दिन का एक शो ऐसा होना चाहिए।

टीवी न्यूज भी सबटाइटल के साथ जारी करने की मांग पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आपका काम सैल्यूट करने लायक है लेकिन लाइव न्यूज में यह कैसे लागू होगा। संस्था के वकील ने कहा कि लाइव न्यूज में न भी हो तो कम से कम दिन में एक बार टीवी न्यूज सबटाइटल के साथ जारी की जाए।

15 मार्च को सिनेमा के बारे में अधिसूचना जारी की

एएसजी ऐश्वर्या ने केंद्र की ओर से 2020 में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कुछ समय दिया जाए वे नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गत 15 मार्च को सिनेमा के बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसमें सबटाइटल जारी करने की बात कही गई है।

हालांकि न्यूज चैनल के लिए ऐसा करना अभी अनिवार्य नहीं किया गया है लेकिन 40 टीवी चैनल हैं जो सप्ताह में एक बार साइन लैंग्वेज में समाचार प्रसारित करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

इस पर पीठ ने सवाल किया कि दूरदर्शन दिन में एक बार सबटाइटल के साथ न्यूज क्यों नहीं प्रसारित कर सकता। भाटी ने कहा कि दूरदर्शन के पास भी कई बार बाहर से फीड आता है। वह इस पर निर्देश लेंगी। पीठ ने कहा कि दूरदर्शन ऐसा कर सकता है, वह प्रसार भारती से निर्देश लें।

अटल भू जल योजना अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। अटल भू जल योजना अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति सभागार शाहपुरा में जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भीलवाडा के तत्वाधान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (IMTI) कोटा द्वारा किया गया1 प्रशिक्षण कार्यक्रम मे अटल भूजल योजना के नोडल अधिकारी डॉ. मदन सिंह राणावत भूजल विभाग ने योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं योजना मे अब तक हुई प्रगति से सभी सहयोगी विभागों को अवगत करवाया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी लाइन विभाग के अधिकारियों व आए हुए प्रतिभागियों को डीएलआई #1,2,3,4,और 5 की वर्तमान स्थिति एव वित्तीय वर्ष 2024-25 मे अर्जित लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया. अटल जल MIS पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024 -25 के सम्पादित कार्यों को अधतन करने की जानकारी प्रदान की 1 ग्राम पंचायत से आए हुए ग्राम विकास अधिकारियों से प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, की कैसे अटल भूजल योजना द्वारा जन भागीदारी के माध्यम से गिरते हुए भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता हैं। कृषि एव उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जल बचत की गतिविधियां जैसे पाइपलाइन, ड्रिप, फव्वारा, फार्म पोंड आदि पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी प्रदान की।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीपीएमयू से आईईसी एक्सपर्ट ने वर्षामापी यंत्र, एव भुजल मापक यंत्र के बारे में बताया। साथ ही अटल जल एप के उपयोग के बारे में जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान योजना से जुड़े पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जन. स्वास्थय अभियात्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, कृषि विभाग , उद्यान विभाग, और वन विभाग के अधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, भीलवाड़ा से मुकुलपुरी गोस्वामी तकनीकी सहायक, आईईसी विशेषज्ञ फारुक मोहम्मद रंगरेज व कृषि विशेषज्ञ राधेश्याम कुमावत और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आदि उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023